THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI):Now, Shri R.N. Arya is the next speaker. ...*(Interruptions)*... I think he can speak tomorrow. After him Mr. Vahadane will speak. आपका समय नहीं है। लेकिन हमारी घड़ी और यहां की घड़ी में फर्क है। उस लिहाज से आपका भी एक मिनट समय है। यहां की घड़ी में तो समय खत्म हो गया है, मेरी घड़ी में आपका एक मिनट का समय है। मेरे विचार में इसको कल ले लिया जाये क्योंकि ड्राउट का मामला बहुत सीरियस है। आप कल बोलेंगे।

**श्री रमा शंकर कौशिक** (उत्तर प्रदेश) : सर, मुझे भी एक मिनट बोलना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): Tomorrow Shri R.N. Arya will be the first speaker followed by Mr. Vahadane and Mr. Rama Shanker Kaushik who will speak for one minute. Now we move on to the Short Duration Discussion.

---

## SHORT DURATION DISCUSSION

### Drought and famine conditions in various parts of the country, particularly in Gujarat and Rajasthan.

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह अजीब विडम्बना है कि हम सदन में वर्षा ऋतु में बाढ़ पर चर्चा करते हैं और ग्रीष्म काल में सूखे पर चर्चा करते हैं। हम प्रति वर्ष चर्चा करते हैं लेकिन किसी निदान और निराकरण पर नहीं पहुंच पाते हैं। स्थिति ज्यों की त्यों रहती है और अभी फिर देश के अनेक राज्यों में सूखे और अकाल की वजह से हा-हाकार मचा हुआ है। जो प्रभावित लोग हैं वे अपनी पीड़ा की व्यथा कह नहीं पा रहे हैं, जो पशु-पालक हैं वे अपने पशुओं को चारा-दाना न देने की वजह से उन्हें मुक्त विचरण के लिए छोड़ दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस भयावह स्थिति से निपटने में केन्द्र सरकार पूरी तरह से असफल रही है।

असफल मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो आपदा है यह एकदम नहीं आई है। इससे निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त सूचना थी। सरकार पर्याप्त समय में सही आकलन नहीं कर पाई, सही कदम नहीं उठा पाई। यही वजह है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब हम यह कह रहे हैं कि यह स्थिति भयावह स्थिति में पहुंच गई है और यही वजह है कि राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोग सूखे और अकाल की चपेट में हैं। वहां पर लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के पानी की तो

यह स्थिति हो गई है कि त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं अपने प्रदेश, मध्यप्रदेश की बात कहना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में लगभग 3,240 गांव इस सूखे की चपेट में आए, खरीफ की फसल के उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई जिसमें सोयाबीन और मक्का आदि फसलें आती हैं। मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र से 361.60 करोड़ मांगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि माननीय कृषि मंत्री जी जिस प्रदेश से होने का दावा करते हैं, उन्होंने मात्र इस स्थिति से निपटने के लिए 29 करोड़ ही स्वीकृत किए। यह अकाल और सूखा भी राजनीति के प्रपंच से बच नहीं पाया। यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे अपने प्रदेश को, जो माननीय कृषि मंत्री जी का भी है, उसको एक राजनीतिक चश्मे से देखा गया है और जो राशि प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई थी, वह स्वीकृत नहीं की गई। यद्यपि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस स्थिति से निपटने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं, तकावी दी जा रही है, गांव में नाला बंधन के लिए राशि आबंटित की जा रही है, पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग साढ़े सात करोड़ रुपया प्रदान किया गया है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिला- कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। बहते हुए पानी के संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होती है उस राशि के अभाव में मानवीय पहल नहीं हो पा रहा है। अब मैं उस प्रदेश राजस्थान की बात करूंगा जिसमें लगातार तीसरे वर्ष सूखा पड़ा है। वहां पर स्थिति यह है और जो न्यूज पेपर्स में छपा है कि मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है। जो मवेशी मर गए हैं, उनका खून वहां के मवेशी पी रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत दर्दनाक है। इसमें लगभग 36 जिले प्रभावित हुए हैं। वहां के मुख्य मंत्री ने 1,0145 करोड़ रुपया मांगा, लेकिन उनको मात्र 102.93 करोड़ रुपया प्रदान किया गया। वहां पर प्रभावित गांव 23,406 हैं। वहां पर राहत गतिविधियां चलाने के लिए, पशु संरक्षण आदि के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की मांग राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा की गई लेकिन केन्द्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गुजरात का जिक्र विशेष उल्लेख के माध्यम से श्री अहमद पटेल जी ने किया है। वहां पर भी स्थिति यही है। वहां पर पानी का संकट पहली बार नहीं आया है, अनेकों बार गुजरात के लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ा है। लगभग 17 जिले प्रभावित हुए हैं और कुल गांव हैं 9,322 । उनमें से लगभग 5171 गांव भी इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। गुजरात में तो हालत यहां तक हो गई है कि पानी के लिए छीना-झपटी शुरू हो गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और अकेले कच्छ में लगभग पांच हजार पशु मारे गए हैं।



16---160/RS/ND/2000

प्रधानमंत्री जी उस राज्य में दो बार हो आए, एक बार हो आए दो दिन के लिए। लेकिन मैं नहीं जानता क्या कारण था कि सूखे और अकाल से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वे नहीं गए । यदि वे दौरा करते और उन इलाकों का दौरा करते जहां पिछले 53 वर्षों में सत्रहवीं बार सूखा पड़ा है जैसे सुंदरनगर तो जो 900 करोड़ रुपये वहां के मुख्यमंत्री ने मांगे हैं और केवल 55 करोड़ रुपये दिए हैं तो शायद उनके मन में कुछ दया आती । न केवल वे गुजरात के लिए बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ पैसा कैलेमिटी फंड से देने की बात करते । मैं उस उड़ीसा का जिक्र करना चाहूंगा जहां ताप बढ़ने के साथ-साथ जल स्तर संकट भी बढ़ रहा है, पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है । उसका एक कारण माइनिंग है, दूसरे और भी कई कारण हैं । आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की खबर भी है । लगभग 18 जिलों के 688 मंडल प्रभावित हुए हैं । एक तरफ हम साइंस टेक्नोलोजी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम इस सदन में विमानों के हाइजैक की चर्चा कर रहे हैं और दूसरी ओर इस देश के अनेक राज्यों में जहां सूखे और अकाल की वजह से एक दर्दनाक स्थिति निर्मित हो गई है उसके किसी निराकरण की ओर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं । इसके लिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हम दो भागों में योजना बनाएं- एक अल्पकालीन योजना बनाएं तथा एक दीर्घकालीन योजना बनाएं । अल्पकालीन योजना में हम आपातकालीन योजना भी बनाएं और उसमें हम यह तय करें कि अभी फिलहाल हम क्या कदम उठा सकते हैं । मेरा अपना यह सोचना है कि जब हम अल्पकालीन योजना का जिक्र करते हैं यद्यपि सरकार ने यह घोषणा की है कि वे खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, एक लाख टन । यह जब तक पहुंचेगा तब तक वहां क्या हालत हो जाएगी ? इस आपातकालीन योजना के जरिए शीघ्रातिशीघ्र वहां के प्रभावित लोगों को पानी, चारा और खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है । जहां पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, जल स्तर यहां तक पहुँच गया है कि हम कितने ही ट्यूबवैल खोदें, कितनी ही फुट तक खोदें पानी नहीं मिल पा रहा है । वहां ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कैसे पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, हम इस बारे में विचार कर सकते हैं । एन.जी.ओज को, बिजनेस ग्रुप को, सोशल ओर्गेनाइजेशन को और भी कुछ फोरेन एजेंसीज से संबंधित ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस भयावह स्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं । उनका किस ढंग से डेवलेपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन आपातकालीन योजना के अंतर्गत करें, इस बारे में सरकार विचार करे । लोगों को वाटर शेड डेवलेपमेंट योजना के लिए और ग्राउण्ड वाटर रिच हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, ग्राउण्ड वाटर के संग्रहण करने के लिए, किस ढंग से जन भागीदारी करके इस समस्या का हम निदान निकाल सकते हैं चाहे वह वाटर

हार्वेस्टिंग योजना हो ? इस प्रक्रिया में हम अपनी टेक्नोलोजी का किस ढंग से उपयोग कर सकते हैं इस बारे में हम अल्पकालीन योजना के तहत विचार कर सकते हैं । जहां तक दीर्घकालीन योजना का सवाल है हमें विचार करना होगा कि पानी बढ़ाने का काम कैसे किया जाए । जब मैं पानी बढ़ाने की बात कर रहा हूं तो जन संग्रहण वाटर मैनेजमेंट स्कीम की बात आती है, ग्राउण्ड वाटर के संग्रहण की बात आती है । साथ ही जल का कैसे हम लोग उपयोग करें इस बारे में लोगों के बीच में एक अवेयरनैस प्रोग्राम चलाएं । वाटर इंटेन्सिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे स्थानों पर खोलने की इजाजत न दी जाए जहां आलरेडी सूखा पड़ चुका है, जहां पीने के पानी की समस्या है । इस बारे में निर्देश संबंधित सरकारों को दिए जाएं । वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोगों को अविलंब कदम उठाने के लिए पहल करनी पड़ेगी । साथ ही हम लोग जो दूर के गांव हैं, वहां पाइप से जल सुविधा उपलब्ध कराते हैं । कई बार देखते हैं कि हम लोग इंटेसिटी वाला मैटीरियल यूज करते हैं, जिससे पाइप में लीकेज होता है । वाटर रास्ते में गिर जाता है उससे हम लोग बचें । इन सब बातों के बारे में हमें दीर्घकालीन योजना बनाते समय विचार करना चाहिए ।

महोदय, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि कई बार इस संबंध में वर्कशाप हुए हैं। जो टैक्नालाजी के एक्सपर्ट हैं, जो वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर बार इस बारे में अपना मत व्यक्त किया है कि वाटर का एक्सप्लाइटेशन बंद करने के लिए और पानी का संग्रहण करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। जब हम सोशल आर्गनाइजेशन के इन्वाल्वमेंट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो सत्य साईं बाबा का ट्रस्ट है जो 250 एकड़ इलाके में है और लगभग 730 गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उसके माध्यम से जो काम हुआ है, उसको देखते हुए कुछ और बिजनेस ग्रुप और सोशल आर्गनाइजेशन और एक्सटर्नली एडिड जो प्रोजेक्ट हैं उन को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए । इस बारे में हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिन राज्यों में सूखा और अकाल पड़ा है, जब इन राज्यों के सदस्य बोलेंगे तो वे बतायेंगे कि वहां कितने हैंडपंप खराब पड़े हैं और कितने हैंडपंपों से अभी पानी ही नहीं निकल पाया है । मैं ऐसा सोचता हूं कि हैंडपम्प के मेंटिनेंस के लिए हमने प्रभावी मशीनरी का उपयोग नहीं किया है । प्रभावी मशीनरी के उपयोग से मेरा मतलब यह है कि हमने लोगों को समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया है । गांवों में, जैसा कि मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, जहां जहां हैंडपम्प खराब पड़े हैं उनका ठीक से मेंटिनेंस करने के बाद लोगों को उनसे पानी मिल जाता है । इसके लिए जो टेक्नालाजी हमारे पास उपलब्ध है उसका कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में भी हमको कदम उठाने चाहिए ।

एक और बात है, हमेशा जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात आती है कि विभिन्न राज्यों में वाटर डिस्प्यूट है उसके सिलसिले में भी जब हम सूखे और अकाल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके कारण पशुओं के उपयोग में आने वाले पानी का कम होना और चारे की कमी होना है । जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार वाटर डिस्प्यूट ऐक्ट में संशोधन करने पर एक बार विचार करे जिससे केंद्रीय संरकार और ज्यादा अधिकार के साथ उन राज्यों के बीच में, जिन में वाटर डिस्प्यूट है, उसको निपटाने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप कर सके और आवश्यक कदम उठा सके क्योंकि कई राज्यों की ऐसी स्थिति है, यद्यपि वहां पीने का पानी अपार है, बाकी पानी भी बहुत ज्यादा है लेकिन वे उसका उपयोग आम किसानों के लिए नहीं कर पा रहे हैं और वह पानी समुद्र में चला जाता है । इसके लिए कई कमेटियां बनीं लेकिन इन डिस्प्यूट्स को हम नहीं निपटा पाए हैं। जहां तक वेस्ट वाटर की बात है उसकी रीसाइकिलिंग प्रापर ढंग से नहीं हो पाती है । जो नान-डोमेस्टिक यूज किया जाता है उसके लिए हम इस पानी का उपयोग करें। लेकिन जिस पानी का उपयोग डोमेस्टिक परपज के लिए किया जाना चाहिए इसको कैसे किया जाए इस के लिए दीर्घ कालीन योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए एक तरफ जब हम रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने की बात करें तो वहीं इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है । अरबन वाटर सप्लाई और रूरल वाटर सप्लाई हमारी एवीडब्ल्यूएसपी और एआरडब्ल्यूएसपी स्कीम बनी हैं और नाइंथ फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत लगभग 86.74 जो गांवों की पापुलेशन है, उनको सैफ वाटर प्रोवाइड करने के संबंध इसका जिक्र था । लेकिन अभी जो स्थिति हमारे देश की है उससे नहीं लग पा रहा है कि जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है उसका जो लक्ष्य था उसको हम पूरा कर पायेंगे । इसके लिए कई कमेटियां बनीं, सुदर्शन कमेटी बनी लेकिन उसके सजेशंस पर भी विचार नहीं हो पा रहा है । साथ ही जो ग्राउंड वाटर के एक्सप्लाइटेशन को रोकने के लिए एक मोडिफाई माडल बिल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री लाई हैं लेकिन उसका भी परिपालन नहीं हो पा रहा है । इसलिए मेरा आग्रह है कि जब हम पानी की कमी का जिक्र करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से और चाहे जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में जो कमेटियां बनें उन कमेटियों के सुझावों पर भी हम लोग गौर करें । अंत में मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल वाटर ग्रिड के लिए जो सुझाव आया कि ऐसे रीजंस में जहां अतिरिक्त पानी है, जहां एक्सेस वाटर है, उसका सदुपयोग उन क्षेत्रों में कैसे किया जाए । जहां पानी की कमी है उसके लिए डा. के.एल.राव कमेटी ने सन् 1972 में सुझाव दिया था, उसका परिपालन नहीं हो पाया। नेशनल वाटर ग्रिड स्कीम के तहत 1980 में कुछ

सुझाव आए थे । उसके बाद इन दोनों सुझावों के परिप्रेक्ष्य में हाशिम कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 30-9-1999 को प्रस्तुत की थी जिसमें विभिन्न नदियों का उपयोग किस तरीके से हो, किस तरीके से पानी का उपयोग उनको इंटरलिंक करने के बाद आम आदमी के लिए, किसानों की फसल के लिए किया जा सकता है, इन सब बातों का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं क्योंकि इस अवसर पर हम सूखे और अकाल की समस्या का जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से अनेक राज्यों में दयनीय और भयावह स्थिति निर्मित हो गई है । इस समस्या के मूल में जो कारण हैं, हमें उन पर विचार करना पड़ेगा और उन पर गौर करते समय इन कमेटियों की सिफारिशों पर भी विचार करें और न केवल उन सिफारिशों पर विचार करें बल्कि एक निश्चित अवधि के अन्दर इन सब सिफारिशों को हम मूर्तरूप भी दें, उनका क्रियान्वयन करें। जब पानी के इंटरबेसिन ट्रांस्फर की बात आती है तो हमारे सामने यह बात आती है कि हम अपने देश में जो रिसोर्सेज़ हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करें । हमारे देश में जो पर्याप्त पानी है उसका उपयोग कैसे हो पाए, इन सब बातों के नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं । इस महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गम्भीर मुद्दे पर बोलने का आपने अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं ।

**श्री लेखराज बचानी** (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, बुजुर्गों से हमने सुना था कि सम्वत् 1956 में पश्चिमी भारत में खास कर के गुजरात, राजस्थान और सिंध में एक गम्भीर अकाल पड़ा था, वैसा अकाल गुजरात और राजस्थान में अभी पड़ा हुआ है । गुजरात में जुलाई मास में इधर-उधर कुछ बारिश हुई लेकिन अगस्त मास बिलकुल ड्राई रहा, कोरा रहा, कहीं भी बारिश नहीं हुई । इस वजह से अगस्त के अंत में गुजरात सरकार ने पशुओं के लिए बहुत सारे घास डिपो खोले और केन्द्र सरकार को 500 करोड़ की मदद के लिए आवेदन-पत्र दिया । अगस्त और सितम्बर पूरा हुआ, बारिश नहीं हुई और अक्तूबर मास में मॉनसून वहां से चली गई। फिर दूसरा आवेदन-पत्र दिया । उसके बाद लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को रोज़ी मिल सके, इसके लिए रिलीफ वर्क भी दिसम्बर, 1999 में राज्य सरकार ने शुरू किये । लेकिन जनवरी तक केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया। जनवरी के अंत में सेंट्रल टीम ने दौरा किया । 31 मार्च को लगभग जब वर्ष पूरा हुआ तब जो गुजरात सरकार का हिस्सा था नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड में 54 करोड़ रुपया गुजरात सरकार को मिला जबकि उससे पहले इस पर 150 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था। हमारी भारत सरकार से विनती है, गुजरात के मुख्य मंत्री महोदय ने दो बार आवेदन-पत्र भेजा है, प्रधानमंत्री को रुबरु मिले हैं । जब सेंट्रल टीम आई थी तब 922 करोड़ की डिटेल उनको दी थी, केन्द्र सरकार को यह डिटेल दी थी कि कैसे कैसे चाहिये। लेकिन अभी तक कुछ राशि नहीं मिल सकी है । अभी आदरणीय सुरेश जी ने

बहुत सी बातें रखीं खास कर के पानी के लिए, गुजरात के ऊपर दया दिखाई और कच्छ के बारे में स्थिति को सामने रखा है। लेकिन पीने के पानी की जो तकलीफ गुजरात में है, मेरा मानना यह है कि नर्मदा डिस्प्यूट अर्थात् सरदार सरोवर का काम पूरा हो जाए, 10 मीटर इसका लेवल ऊपर आ जाए तो केनाल में पानी आ जाएगा । और गुजरात के जो छोटे-छोटे रिजरवायर्स हैं उनको पानी मिलेगा। कम से कम 10 हजार गांवों को, 100 शहरों को, टाउन्स को इससे पानी मिल सकता है। आदरणीय सुरेश जी ने बड़ी बड़ी बातें कीं। उन्होंने इमीडिएट योजनाओं की बात की, लांग टर्म योजनाओं की बात की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इतने वर्ष किसकी सरकार थी, किसने इन्कार किया था? कोई लांग टर्म की योजना क्यों नहीं शुरू हुई? गुजरात सरकार ने पीने के पानी के लिए और इरीगेशन के लिए इस वर्ष बहुत सी स्कीमें चालू की हैं। सौराष्ट्र में कम से कम 2 हजार चेक डैम्स तो बन गए हैं और दूसरे चेक डैम्स बन रहे हैं। 100 करोड़ की राशि स्पेशली ऐसे चेक डैम्स के लिए सौराष्ट्र में गुजरात सरकार ने दी है। गुजरात सरकार ने ड्राऊट स्थिति का ख्याल करके इतनी खातिर दी है पब्लिक को कि दो वर्षों के अंदर गुजरात में पानी की कोई डिफीकल्टी नहीं होगी। लेकिन सभापति महोदय, यह जो डिफीकल्टी गुजरात में पीने के पानी की है वह फख्त दो मास के लिए है और नेक्स्ट इयर हम समझते हैं कि जो योजनाएं अभी कार्यान्वित हो रही हैं, इंप्लीमेंट हो रही हैं वे जब पूरी हो जाएंगी तब गुजरात को पीने के पानी की जो डिफीकल्टी अभी है वह कम हो जाएगी। आदरणीय सुरेश जी अपनी मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ सजेश्चन दें। यह देश की बात है, यह राष्ट्रवाद की बात है। बरसों पहले एक अवार्ड हुआ था। उस वक्त चार स्टेट सरकारों और सेंट्रल गवर्नमेंट में वह अवार्ड हुआ था। कोई एक रिहैबिलीटेशन का सवाल था, मुद्दा था। वह भी सुप्रीम कोर्ट में अभी देखा गया है। अगर सही बात देखें तो नर्मदा की जो बात है या डिस्प्यूट है, अगर यह क्लियर हो जाए तो गुजरात एक नन्दनवन हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो आज की सरकार है वह गुजरात को सुखी, आनन्दमय और नन्दनवन परिस्थिति में देखना नहीं चाहती है। इसलिए मैं विनती करना चाहूंगा कि आप कम से कम अपनी सरकार को कुछ तो परसुएड करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगा। लेकिन कम से कम अब जब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यह एक नेशनल प्राब्लम है। आपको कम से कम यह देखना चाहिए। लास्ट मानसून में नर्मदा में दो बार फ्लड आया और जिलियन्स आफ क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में चला गया। अगर यह कुछ काम हो गया होता, कुछ डैम की लेविल ऊपर आयी होती तो यह पानी पीने के लिए कैनाल के मारफत और रिजरवायर के जरिए लोगों को मिल सकता था। आपने हमको इससे महरूम रखा है। इसलिए बार बार मैं यह कह रहा हूं।

दूसरी बात गुजरात सरकार ने जो मांग रखी है केन्द्र के पास वह अगर देखेंगे तो 17.1.2000 को जब केन्द्र से टीम आई तब डिटेल में 922 करोड़ की जो बात की उसमें अलग अलग बातें बतायी गयी। रिलीफ वर्क के लिए 375 करोड़ की मांग की है और उसके लिए कितने मानव दिन रोजगार चाहिए वह क्लियर बताया गया है। कम से कम 10.88 करोड़ मानव दिन रोजगार के लिए कुछ सहायता चाहिए। उसमें से कुछ गुजरात की सरकार ने इस साल काम स्टार्ट किए हैं। लेकिन गुजरात की फाइनेंशियल जो स्थिति है वह लिमिटेड है इसलिए केन्द्र से यह जो विनती की गयी है, केन्द्र को तुरंत किसी भी आयोजन से, अगर नेशनल कैलामिटी फंड हो तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल कोई राशि देनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात एक कृषि प्रधान राज्य है और 70 परसेंट जो देहात में लोग रहते हैं वे किसान हैं अथवा किसान मजदूर हैं। इस बार मानसून फेल हो गया। वहां इरीगेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं है, हार्डली 23 परसेंट की जो इरीगेशन की फैसिलिटी है वह भी मानसून के फेल होने से नहीं रही है। तो यह सीजन जो है वह फेल हो गया है और आज 10 हजार गांव गुजरात में - जो 50 परसेंट से ज्यादा हैं, वहां सरकार ने ड्राऊट स्थिति डिक्लेयर की है। गुजरात सरकार ने अपनी ओर से कुछ काम शुरू किए हैं और गुजरात के एन.जी.ओज. ने वी/जेजेजे-3 इनीशिएशन लिया है। मैं आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहता हूं कि लास्ट 50 वर्ष में जब देश में किसी राज्य में कोई भी कैलामिटी आयी है चाहे बिहार हो अथवा उड़ीसा हो, लातूर हो, कारगिल हो या काश्मीर हो ...।

जब उड़ीसा में ऐसी परिस्थिति आई तो दो-दो, तीन-तीन ट्रेनें साधन-सामग्री गुजरात सरकार ने भेजी थी, एन.जी.ओज़ ने सहायता की थी लेकिन अभी तक गुजरात में किसी दूसरे प्रांत से किसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मदद की हो, ऐसा सुनने को नहीं मिला है । इसलिए मैं आपके माध्यम से और इस हाऊस के माध्यम से सारे देश से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम इस अकाल की स्थिति में गुजरात में जहां पचास परसेंट से ज्यादा विलेज अफेक्टेड हैं, पूरे देश को और दूसरे जो एन.जी.ओज़ हैं, जैसे अभी बात की गई, आंध्र प्रदेश में सांई बाबा इंस्टीट्यूट है और दूसरी जो संस्थाएं हैं, उनको गुजरात की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं कच्छ की रण है । वहां कभी बारिश होती है तो इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है और कभी नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। हर तीन वर्ष पर गुजरात में सूखा

पड़ता है । कई ज़िले तो ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बहुत डिफिकल्टी है । मैं केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मेरे ज़िले बनासकांठा में दो रीजनल वाटर स्कीम्स हैं। एक स्कीम से 200 गांवों को पानी मिलता है और दूसरी स्कीम से 157 गांवों को पानी मिलता है । वहां ट्यूबवेल लगाए गए हैं लेकिन जब पावर ट्रिपिंग होती है तब जो बोर चल रहे होते हैं, वे बंद हो जाते हैं और उनको रीस्टार्ट करने में बहुत टाईम लग जाता है। इसलिए सरकार को इसके लिए कुछ मदद करनी चाहिए । वहां जेनरेटर्स लगाने के लिए कुछ स्पेशल राशि गुजरात सरकार को दी जानी चाहिए । जहां-जहां ये रीजनल स्कीम्स हैं, जहां-जहां ये पावर ट्रिपिंग होती है, उसके लिए कोई आल्टरनेट व्यवस्था हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री महोदय से।

महोदय, गुजरात में यह जो अनियमित मानसून आया, उसके कारण 16 ज़िले अफेक्टेड हैं और गुजरात के 176 तालुकों में से 153 तालुके अफेक्टेड हैं । पीने के पानी की जो परिस्थिति बताई गई, उसके लिए कहा गया कि वह हम ट्रेन से भेजेंगे । ठीक है, ट्रेन से दे सकते हैं लेकिन जहां ट्रेन नहीं जा सकती, जैसे मेरा ज़िला है या जो क्षेत्र पाकिस्तान के नज़दीक हैं, वहां कोई रेलवे लाईन नहीं है तो वहां पानी कैसे पहुंच सकता है? इसलिए हर एरिया के लिए पानी ट्रेन से भेजना कोई आल्टरनेट नहीं है । हां ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था कि गांधी नगर से राजकोट तक पानी ट्रेन द्वारा भेजा गया था क्योंकि वहां सीधी रेलवे लाईन जाती थी लेकिन ऐसा हर जगह के लिए संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात में 174 रिज़र्वायर हैं जिनमें से 3 रिज़र्वायरों में दो परसेंट पानी ही बचा है और बाकी सब सूख गए हैं । गुजरात के सारे रिज़र्वायर सूख गए हैं। आने वाले वर्ष के लिए गुजरात सरकार ने तालाब खोदने के लिए और जो तालाब अभी हैं, उनको और डीप करने के लिए, वाईड करने के लिए बहुत स्कीमें बनाई हैं । हो सकता है कि भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति का गुजरात सरकार और उसकी पब्लिक सामना कर सके लेकिन हम तो सिर्फ दो महीनों के लिए मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार दो महीनों के लिए गुजरात सरकार की सहायता करे जो उसकी तरफ से मांग आई है, डीटेल में सारे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

महोदय, गुजरात में जो ग्राउंड लेवल वाटर है, वह बहुत नीचे जा रहा है । उसकी ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि वहां डार्क ज़ोन कहां है ग्रे ज़ोन कहां है और व्हाईट ज़ोन कहां है ? गुजरात में कुछ ज़िलों में इतना डार्क ज़ोन हो गया है कि वहां 85

से 100 परसेंट पानी एक्सीड हो रहा है, तो ज्यादा पानी मिलेगा कहां से ? और जो ग्रे जोन 65 टू 85 परसेंट हैं वहां भी देखेंगे तो वह भी डार्क जोन हो जाएगा और व्हाइट जोन जो है वह ग्रे जोन हो जाएगा । इसलिए ये री-चार्जिंग और प्रिज़र्वेशन ऑफ़ वाटर के लिए भी कुछ स्कीमें की जाएं । केन्द्र सरकार ने जो वाटर शैड की स्कीम अभी दी है और गुजरात को मदद दी है और दे रहे हैं, वह सराहनीय है । मेरे जिले में वाटर शैड इतने बन गए हैं कि अगर बारिश हो जाए तो उस बारिश का पानी वहां रोक सकते हैं और लोग अपनी इन्कम भी ले सकते हैं । लेकिन अगर बारिश ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे ? इस वजह से गुजरात का जो वाटर लेवल है उसके लिए भी केन्द्र सरकार को कुछ देखना चाहिए। अभी 21-22 तारीख की, चार रोज़ पहले की बात है, यहां से एक जो रूरल डिवेलपमेंट मंत्रालय का ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है, उसके इंजीनियर्ज़ और आफिसर्ज़ वहां आए थे। वे जामनगर, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में जाकर देख कर आए हैं कि वहां पीने के पानी की कितनी डिफिकल्टी है । वह रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई होगी । सरकार उसको बराबर देखे और गुजरात को मदद दे । गुजरात सरकार तो कैटल्ज़ बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। पहले 5 रुपया घास चारे के लिए पर कैटल देते थे, अभी आठ रुपया कर दिया है, लेकिन एक गाय के लिए, एक भैंस के लिए 20 रुपया रोज़ चाहिए। एनजीओज़ कितनी मदद कर सकती हैं? इसलिए कैटल्ज़ को बचाने के लिए भी कुछ मदद होनी चाहिए । यह आठ और बीस रुपये में बहुत फर्क है । गुजरात सरकार का मैंने पहले ही कहा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ होने के कारण वह इतनी मदद कर नहीं सकती है, इसलिए केन्द्र से हम मदद मांग रहे हैं । पीने के पानी के लिए 311 करोड़ की मांग की है । अभी यह देना है या नहीं देना है, यह सरकार पर निर्भर है, क्योंकि अभी 21-22 तारीख को जो अधिकारी आए थे वे सब देख गए हैं । इसलिए इसमें से जितनी राशि आप दे सकते हैं वह जल्दी से जल्दी गुजरात सरकार के लिए रिलीज़ करें ताकि जो काम अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो काम जल्दी करने चाहिएं, वे पूरे हो सकें । अभी पानी के लिए जो बोर करना चाहिए उसके लिए भी पैसा चाहिए । गुजरात सरकार ने इमीडिएट और लॉंग टर्म, दोनों तरह की स्कीमें चालू की हैं । जो हमारी लॉंग टर्म योजना है उसके लिए हम अभी नहीं मांगते हैं, लेकिन इमीडिएट जो हमारी स्कीम्ज़ हैं उन्हें पूरा करने के लिए अभी हमारी डिमांड है और उसके लिए हमको कहना पड़ता है । वैसे तो हैंडीक्राफ्ट्स के जहां काम चलते हैं, वहां पर तो बहनें और भाई अपने घरों में बैठ कर काम कर सकते हैं । उसके लिए भी गुजरात सरकार ने कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ मदद चाहिए । जो रिलीफ वर्क है जहां पहले 30 रुपये नहीं मिलते थे तो वहां

गुजरात सरकार ने 40 रुपये देने का निर्णय किया है । मैंने पहले ही कहा कि 11 करोड़ मानव दिन रोज़गार हमको देना पड़ेगा । ....**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी)**: बचनी जी, अपनी पार्टी के कुछ दूसरे सदस्यों का भी ख्याल रखिएगा ।

**श्री लेखराज बचानी**: हां । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हमने राहत के काम के लिए 375 करोड़ रुपये की मांग की है इसमें भी जो मांग गुजरात की है वह पूर्ण करनी चाहिए। फिर मानसून का सीज़न शुरू होगा तो सीड्ज़ के लिए भी सबसिडी देनी पड़ेगी और कैटल के लिए भी सबसिडी देने की जरूरत है । कैश डोल भी दे रहे हैं । कुछ रकम इन्क्रीज़ की है, क्योंकि महंगाई की वजह से ज्यादा देना पड़ा है । वह भी सरकार के ऊपर बोझ आ गया है । उसके लिए भी हमें चाहिए। आरोग्य सेवा है, पशु का आहार है, उसके लिए भी 70 करोड़ की मांग की है। हमारी यह मांग भी पूरी होनी चाहिए । मैं सदन को कह सकता हूं कि नैक्स्ट ईयर चौमासा अगर कठिन भी आएगा तो भी हम परिस्थिति का सामना कर सकेंगे । लेकिन यह तो जो लास्ट मानसून है यह टोटली फेल होने की वजह से डिफिकल्टी हुई है ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन. चतुर्वेदी)**: बचनी जी, यह आपकी मेडन स्पीच है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया है ।

**श्री लेखराज बचानी**: महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से को निवेदन है ....**(व्यवधान)**...

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, the Minister concerned is not in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): The Leader of the House is there. लीडर ऑफ् द हाउस तो हैं । .....**(व्यवधान)** वे अभी-अभी गए हैं ।

Two other Ministers--the Minister of Culture and the Minister of Water Resources--are also there, noting down the points.

**श्री लेखराज बचानी**: उपसभाध्यक्ष जी; अंत में मैं आप के माध्यम से आदरणीय सुरेश पचौरी जी से विनती करना चाहता हूं कि अगर गुजरात के लिए आप के मन में कुछ मान है, स्थान है और दया भाव है तो नर्मदा के प्रश्न के शीघ्र समाधान की दिशा में प्रयास होनी चाहिए । ...**(व्यवधान)**...आप ने खुद ही बोला कि लांग-टर्म योजना की आवश्यकता है तो लांग टर्म योजना तो यही है, दूसरी तो कोई ऐसी योजना नहीं है । उपसभाध्यक्ष जी,

**5.00 P.M.**

वहां का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है । अब आप कितना रिचार्ज करेंगे, कितना प्रिजर्व करेंगे और कितना कनजर्वेशन करेंगे ? हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज बस्ती बढ़ गयी है और पीने के पानी की मांग बढ़ गयी है । इतने वर्षों में जब आप का शासन था, आप ने जमीन में पानी नहीं जाने दिया और बारिस का पानी चला गया । इसलिए गंभीरतापूर्वक इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया । साथ ही पार्टी व्हिप को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया । धन्यवाद ।

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Sir, we are facing an alarming situation in our country-- the severe drought leading to a famine. It is said that we have not seen such a situation in the recent past. Horrifying news has been pouring in, both in the print media and the electronic media, and also the first-hand study. I come from Andhra Pradesh. I would like to concentrate more on the situation prevailing in Andhra Pradesh. But, at the same time, I am speaking on behalf of my party. So, I will have to touch the other aspects and other States also. We have received a report from Rajasthan saying that all the PDS shops are empty.

Secondly, people are getting down into the wells to draw water and one or two deaths have been reported recently of people slipping into the open wells. The third important point reported was that there were water riots in the State. Because of lack of fodder, cattles are dying in hundreds and thousands, and there is migration of people to the nearby places and towns. Out of 32 Districts, 26 Districts have been declared drought-affected. In Gujarat, about 8500 villages have been declared to be drought affected, and the interesting feature here is, most of the dams meant for drinking water, have completely dried up. Here also, there have been water riots and there was some firing reported where one or two people were reported to have died. Because of scarcity of water, the water is most polluted and the people drinking the polluted water are getting the gastroenteritis desease. Today, I read a report about the Gir Forest which is the sole sanctuary of the Asian Lions. I had the opportunity of seeing the forest some time back. It is a beautiful area. But the pathetic situation there is that both men and wild animals are competing with each other for drinking water. It is said that in Baroda, in Gujarat, water is being sold by one of the former ex-rulers to his

ex-subjects, and the municipality and the Government authorities are unable to explain the situation as to why a particular individual could sell water to the people because of shortage. I would like to quote a news-item which has appeared in the Press wherein the Chief Minister of Gujarat had stated that there is absolutely no crisis in any part of the State. At the same time, he has admitted the failure of the local administration. I do not know if it can be termed as a case of slumber kor self-deception. The Government of India's belated gesture of carrying water by trains to some of these areas and issuing 20 kgs of foodgrains to people in the affected areas, I am afraid, has come very late.

I am afraid it has come very late. They should have come to Parliament with a suo motu statement of the famine situation in this country, some ten or fifteen days back. I was trying to raise this question about Andhra Pradesh for the last ten days. Unfortunately, I did not have the opportunity, but that is a totally different matter. They should have come to this House, instead of going to the public and appealing for donations to get over this situation. It is all right; the people can donate for such a cause, but at the same time, the responsibility of the Government is that they should have come and put it before Parliament for discussion. Because what we need in this situation is a consensus among all political parties and only that can get us out of the situation.

We have always been hearing about Kalahandi, in Orissa. Obviously, not for good reasons. There also, about a temperature of 45 degrees has been reported and people have become victims of various diseases due to water scarcity.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

Then I come to the pathetic situation in my own State. The condition of the people in some of the districts is very miserable. About 18 districts have been declared to be drought-affected. Around 688 mandals, which means, about two-third of the State of Andhra Pradesh, have been declared as drought affected. During the last one year, Sir, the shortfall in rains in various places is to the extent of minus 90 per cent of the average rainfall. The Government of Andhra Pradesh had declared, in stages, the names of many mandals. And the figure now comes to 688 mandals, that is, about 40 lakhs of families are affected by this drought. The crops in the districts of Anantapur, Mahabubnagar, Rangareddy, which mostly grow groundnuts, red

grams and beetle leaves, have compleltely withered away in the kharif season. There is no possibility of sowing again in the rabi season. The ground water level had receded in most of the places. The irrigation wells, open as well as bore wells, in most of the villages have dried up. People are forced to fetch water from a long distance. Particularly, women are forced to do this job. There is no fodder for the cattle and the peasants are selling away the cattle to the slaughter houses. There is large-scale migration of these people to nearby towns like Tirupati -- it is a very holy city of ours - Bangalore, Hyderabad and to a very distant place like Maharashtra. Starvation deaths have been reported.

A special feature of our State is the suicides that are being committed by the farmers because of the failure of crops, due to which they are facing a lot of poverty. It is very unfortunate that there is pressure from the cooperative societies from where the peasants have got some loans. Pressure is also coming from the private money lenders; the pressure is such that the farmers are driven to commit suicides. So far, during this season, according to one estimate, 140 suicides have been reported. Leave alone the cotton farmers' suicide. It was running into many hundreds; and that was about one year back. I will read from one of the authentic reports published in *The Hindu* . It is not my newspaper. "According to unofficial estimate, the district saw 140 suicides by farmers recently due to pressures for repayment of crop loans. Of them, the Jadcherla areas alone accounted for 14. There have been a total of 800 to 1,000 such deaths in the State during the past three years. The Government has granted Rs. 1 lakh ex-gratia each in 74 cases. Gloom pervades many habitations around Jadcherla."

Sir, during the last three days, we are getting reports of cases of gastro-enteritis and deaths in many parts of the State because of the polluted water. The crop loss is estimated to be about Rs. 2,500 crores, but our State Government had requested the Centre for a grant of about Rs. 750 crores.

But, unfortunately, the Centre had granted only an amount of Rs.75 crores which comes to one-tenth of the amount that the State Government had asked for. I don't know how much money has been released so far from this amount of Rs.75 crores. We don't have the authentic information. You know that the financial position of our State Government, to put it in a respectable term, is precarious. The recent CAG report confirms the very bad financial situation of our State. Therefore, we are unable to meet the situation. One of

the Central Ministers recently said that it was the responsibility of the State to look after some of these aspects of drought, famine, etc. Our CM had, at the same, declared an allocation of Rs.154 crores for these areas. But because of the paucity of funds and financial crunch, only an amount of Rs.53 crores could be released so far and the people say that nothing had reached them, and even that small amount had got just evaporated through the bureaucratic pipelines. Ironically, one responsible Minister of State made a statement. I am sorry to say that that statement has become very controversial. He has attributed these deaths to psychological disorder which has become a communicable disease. This Minister is a doctor and a respectable colleague of mine and he holds the degree which I hold. At the same time, I am disturbed by the poverty of diagnosis of this doctor. My request to the Centre is that it should come to the rescue of the State irrespective of the fact that there are some lapses. We should not go into the technicalities. It is not the time to go into the technicalities. Don't say, "we have already given you money from the NFCR. We have already given you money from the CRF. There is no utilisation certificate. The CAG report supports it. The accounts are not maintained properly. There are diversions of funds." All these things might have happened. But don't stand on the technicalities and say, "because of these things we are not going to give you the fund". When such a situation arises, it is the duty of the Centre to assist the State Governments. The Government knows where to dip its fingers and how to dip its fingers. You only ask a bureaucrat, he will tell you how to do it. The Government of India should come forward immediately, without bothering about the technicalities, to help the State. That is my demand.

Before I conclude, I have one or two points to make. What happened to the National Drinking Water Mission? It was announced long time ago. Now, the whole country is crying for drinking water. What is happening to all these missions? That is my question. Where is the disaster management policy of this Government? Should we, such a large country,not have some policy to manage or pre-empt disasters of this type? We don't see any such things here. What about the long-term strategy? We have perennial rivers. In our State we have the great Godavari river. We have the great Krishna river. They have not been harnessed properly. We have projects which were built 100 or 150 years ago by Sir Arthur Cotton. Fifty per cent of the Godavari water is now going to the sea and we are starving for water. Where is the concept of sustainable development in this country? Now, we

are fighting. Some people say environment is important and fight for it. Some people say development is important and fight for it. But nobody thinks of the importance of combining these two to have sustainable development. We are having some dams which are important for drinking water, for irrigation, for sustenance of our people. Where is the policy of recharging the groundwater level which is receding very rapidly. Some of these things require long-term measures and the Government of India as well as the State Governments should pay attention to it.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, in Gujarat, there are 18,000 villages. Out of these 18,000 villages, 9,000 villages have been severely affected by drought. So, half of Gujarat is under the grip of very severe drought conditions. As the Chief Minister has said, it is the worst drought in Gujarat during the last hundred years. This is the position in Gujarat today. But, Sir, I would like to bring to the notice of this House, how our State Government remained negligent and not alive to the problem, which is of a very serious nature. Sir, in September last, the Meteorological Department announced that the monsoon was over. It means, there was no likelihood of any further rains . The ex-Chief Minister of Gujarat and the present CLP leader, Shri Amar Singh Choudhary, demanded from the State Government that a declaration should be made that since there was scarcity and relief work should be started immediately. But the declaration came on 28th of December i.e. after three months . So, the hon. Chief Minister took three months to apply his mind and decide whether a declaration of such a severe scarcity condition should be made and relief work started or not. Obviously, he was not prepared to start the relief work at that point of time. Therefore, it took three months. After three months, he declared this scarcity condition and then he started the relief work. Then, Sir, the fodder price was Re.1 per kg at the time when the declaration was not made. But when he made the declaration, the price of fodder went up to Rs.5 per kg. And now the situation is that necessary fodder is not being supplied to the persons who are the most affected, whose cattle are dying, starving, for want of fodder and rain. In this connection, I must mention that the Rajasthan Chief Minister wrote to the Centre for granting Rs.1145 crores, in the month of October. In Gujarat, the declaration was made in December. The Rajasthan Chief Minister asked the hon. Prime Minister to give him Rs.1145 crores, as the situation was very serious; in the month of October. He met the Prime Minister personally on November 16, and again on the first day of

February, i.e. he met him twice. Mr. Vice-Chairman, Sir, you will be surprised to know that our Chief Minister did not bother to meet the Prime Minister at all. When the Prime Minister came to Gujarat... ...*(Interruptions)*... Please sit down. He has not met. Why are you defending the Chief Minister. ...*(Interruptions)*... He has not met the Prime Minister. Please take your seat. It is a fact that he has not met the Prime Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI LALITBHAI MEHTA (Gujarat):He met the Prime Minister on 26th of October. He submitted the memorandum personally ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT : Don't try to be a goalkeeper of the State Government who has made a mess of the situation ...*(Interruptions)*... The Prime Minister came for two days. You know this. He came from America. He was in America for 10 days. At a time when Gujarat was burning, he was fiddling in America. He came after ten days, landed in Bombay the same day the Prime Minister was there in Gujarat. Instead of meeting the Prime Minister, my friend, he said 'I am sick.' He became sick the moment he landed in Bombay. He was not courteous enough to send even a Memorandum to the Prime Minister at that time, during those two days. Nor did he send any of his senior Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT Karnataka): As of today the Chief Minister has not met the Prime Minister. ...*(Interruptions)*... He can praise Chief Minister when he speaks. You can say that he has done a very good thing. ...*(Interruptions)*...

SHRI LALITBHAI MEHTA: I am putting the record straight. Sir, he is misleading the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: The record is very straight. As of today, he has not met the Prime Minister. He has not sent even a single Minister to give a memorandum to the Prime Minister on behalf of the State Government. Only once Shri Suresh Bhai Mehta accompanied him. I know that. He has briefed the Prime Minister. Mr. Vice-Chairman, Sir, it is said inGujarat which is known to everybody here that the Chief Minister has not got a good wave-length with the Prime Minister. Whatever is his wavelength with the Prime Minister, we are not concerned.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, the Chief Minister is not here. It is not fair. Sir, he is aware of the rule and precedents of the House. The Chief Minister is not here. If he wants to attack the Chief Minister politically, he can do it outside. We are discussing the drought and famine conditions in various parts of the country. Sir, the people are suffering. Let us not politicize the issue. Let us not unnecessarily dilute the spirit of the debate. Sir, he is a very senior Member.

**श्री रामदास अग्रवाल** (राजस्थान) : इस तरह से आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं है।.....**(व्यवधान)** यहां कहां विषय आ गया चीफ मिनिस्टर का। ....**(व्यवधान)**...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, the Chief Minister has not ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are not discussing here as to what are the differences in the Congress Party or in the BJP. आप संबंधित विषय पर बोलें। He should not speak like that. Let us not play with the lives of the people.

SHRI RAJU PARMAR: Everybody knows as to what is going on in Gujarat.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : भट्ट जी, आप अपने प्वाइंट रखिए।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is why he has got two-thirds majority.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Sir, as of today the Chief Minister has not visited the affected areas of Gujarat at all. He is sitting in the Secretariat in an air-conditioned room. You can see the Chief Minister of Rajasthan going to different villages. Can you advise the Chief Minister to visit the affected areas of Gujarat and see for himself as to what the position is? ...*(Interruptions)*... The fact of the matter is...*(Interruptions)*...

SHRI BACHANI LEKHRAJ: Sir, he has met so many people. He has visited so many areas. ...*(Interruptions)*...

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: What is the position in Rajkot? There were water riots in Rajkot which is the city of the Chief Minister. Thousands of women have ransacked the office of the Municipal Commissioner. Even then what is the position as of today? In Delhi we get

water for two hours in the morning and for two hours in the evening. In Rajkot, water is given for 25 minutes every alternate day. That is the position as of today. They are saying that there is proper management of water. That is what is being done there. That is the position. Water riots have taken place in Junagadh, Bhavnagar, Surendernagar and Jamnagar which are district towns. Water is still not coming there. It is coming every alternate day. Water is given every alternate day in all these district towns. That is the position. The situation is becoming worse and worse. What has happened in Phalna and Jamnagar where three farmers had died because of the firing arising out of water dispute? The same is the situation in Bhavnagar. People there were forced to stall the highway traffic. They are not getting water. Fortunately, the Sub-Inspector escaped. Kerosene was poured on him. He was about to be burnt alive. Somehow, he escaped. But his motorcycle was burnt. This is the position. This is the ground reality. Water is supplied to 2000 villages through tankers.

And, what is the experience? Tankers come, and they have to be taken again to some other villages. I know of certain instances, particularly, in Kutch, that when a tanker goes to distribute water, and the people are waiting there for the tanker to come, the driver of that tanker would not wait there; instead, he would pour the water into the dry well and ask the people to take the water from there. How would the ladies waiting there draw water from the dry well? That is the serious condition in Gujarat today. Therefore, my submission to this august House, to you, Sir, and to the Government is this. In view of these things, when water is not available, when there are water riots taking place, the Government of Gujarat had sought an assistance of Rs.722 crores from the Central Government, and the Central Government has granted only Rs.54 crores. My submission is that more and more assistance is required.... *(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): When was this demand of Rs.722 crores made?

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: I am pleading the case of the Chief Minister. He has asked for Rs.722 crores, but only Rs.54 crores were given to the State by the Central Government. More and more monetary help is required. Otherwise, Gujarat will be in a very difficult situation. That is what I say. People have started moving from there. A Central team was sent there, and they have given their report. Mr. Chaddha, who was sent from here,

himself has said that the people there do not know anything about water management; they have no expertise; they have no knowledge about recharging of water and so on. But, unfortunately, nothing has been done by the State Government. Sir, I submit that the hon. Prime Minister should visit Gujarat and see for himself how the situation there is. And, if possible, a Parliamentary delegation can visit the State of Gujarat to find out the facts. Whatever I may say or my friends there may say is immaterial. What is the ground reality there? This should be realised. In fact, the ground reality has been expressed by a Cabinet Minister himself, that is, Shri Kashiram Rana. He visited some places, and has stated in a news report on 23rd that Saurashtra, Kutch and North Gujarat are in a very serious drought condition. He has said that the people, including farmers, and the animals have to be removed from that place to a safer place. That is what Mr. Kashiram Rana has said. Water can be sent by trains, as had been done in the past. I would like to add one more thing. There is a report in today's *Times of India* on the front page that the next monsoon is not likely to be satisfactory. If this happens, then, it will be a big catastrophe. The Government of Gujarat as well as the Central Government should take it as a warning. I wish this report is proved false. But it is a warning from the Meterological Department of Bangalore.

Sir, there are also reports in the Press that the Minister has said that the responsibility for this state of affairs is with the State Government. I fail to understand this. How can a Minister say, in this grave situation, that only the State Government is supposed to deal with the situation? If, tomorrow, people die, if there are water riots, will the Minister go on fiddling when the situation there is burning? It is the responsibility of the Central Government to see to it that the people do not die, that the animals do not die, and that there are no water riots.

The Central Government must come to the rescue of the State Government. The State cannot be left to the mercy of the Almighty God. The Central Government must shoulder that responsibility. The hon. Minister should please take note of this.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf the Telegu Desam Party, express my serious concern on the drought and famine conditions in Gujarat and Rajasthan and in various other parts of the country. I may be permitted to bring to the notice of this august

House the drought and famine conditions in Andhra Pradesh. Sir, severe drought conditions are prevailing in Andhra Pradesh due to deficit in rainfall during the South-West monsoon period, i. e. from June to September. Due to the most unsatisfactory distribution of rainfall and long dry spells, most of the major rainfed crops such as groundnut, maize, cotton, castor and sunflower, got damaged severely. A major crop of the State, the paddy, either could not be transplanted or it withered away after transplantation. The value of the loss in terms of area unsown, as well as production loss due to damage to the standing crop, is estimated at Rs.2566.91 crores. Our State Government immediately impressed upon the hon. Prime Minister and requested for Central assistance of the order of Rs.720.36 crores. The Prime Minister was kind enough to immediately depute a Central team headed by the Joint Secretary (Agriculture), Government of India, for an assessment of the drought situation in the State. The Central team visited the drought affected areas of the State in the first week of October and held detailed discussions with the officials, the public representatives and the public. The Central assistance of Rs.75 crores from the National Fund for Calamity Relief was announced long back but, unfortunately, it was credited to the State's Head of Account very late, on 31st of August, 2000. As of today, almost the entire State of Andhra Pradesh is reeling under one of the worst droughts in recent times. The ground water table is depleting very fast. The fall in ground water level, as recorded in March 2000, is about 13 metres as compared to the one prevailing in March 1999 and the maximum fall in the ground water table is likely to touch 20 metres or even more by May-June 2000. Already about 14000 bore-wells have completely dried up. 619 Protected Water Supply Schemes have failed due to source failure. As on today, many parts of the State are facing acute scarcity of drinking water and it is likely to be further acute in the coming two months. Already transportation of drinking water has been undertaken in 1400 villages. Hon. Vice-Chairman, Sir, due to scarcity of fodder, cattle are dying in some parts. The farmers are preparing themselves for distress sale of their cattle. The State Government is opening fodder banks and at selected places some cattle camps also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Reddy, there are three speakers from your party and the allotted time is ten minutes. Please be brief.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Yes, Sir. Sir, we are highly thankful to the Government of India for its concern over the drought

situation and the recent decision to release 20 kgs of foodgrains to each family in the drought affected area at below-poverty-level rates. The other is the 'Food For Work' Scheme, under which individuals would be entitled to 2 kg. of foodgrains per mandays work at the below poverty line rates. These two decisions of the Government of India will definitely help the people in distress in the drought affected regions. There is a talk in official circles that these two programmes are not for Andhra Pradesh, which is largely affected by severe drought conditions. If it is so, this attitude is objectionable, irrational and condemnable. Our Chief Minister has already requested the hon. Prime Minister to implement these two programmes in Andhra Pradesh also. I appeal to the hon. Prime Minister to announce in the House itself that these programmes will also be implemented in the drought-affected parts of Andhra Pradesh. I am sorry to note that the severe drought in Andhra Pradesh is not being considered at par with the other drought affected States. In Andhra Pradesh, 18 districts are affected by drought as against 22 districts, 688 mandals as against 1099 mandals and 17431 villages as against 21,865 villages are affected by severe drought and the State Government has declared them as drought affected areas and it is implementing the drought relief programmes. Hence, I appeal to the Government of India to treat Andhra Pradesh drought affected areas on par with other affected States. Our State Government has spent about Rs.400 crores for the drought relief including the assistance to the farmers, drinking water supply, fodder for the animals and employment generation for the poor. Our Chief Minister is personally monitoring regularly the drought relief programmes and he has already visited four districts. I appeal to the hon. Prime Minister to come to the rescue of Andhra Pradesh by immediately releasing the remaining amount of Rs.645 crores for continuation of relief measures started by Andhra Pradesh Government. I would further appeal to the Government of India to release the Ist and the IInd instalments of all the Centrally Sponsored Schemes such as EAS, Watershed Development, JGSY, etc. without insisting on the utilisation certification in respect of the Ist instalment.

**श्री रामदास अग्रवाल** : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अकाल के बारे में कुछ शब्द इस सदन के सामने कहना चाहता हूं। महोदय, राजस्थान के अकाल के बारे में जो भयावह स्थिति है और जिस पर के सूखे की स्थिति बन गई है, इसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। वैसे राजस्थान का रेगिस्तानी हिस्सा हमेश लगभग सूखे की मार में रहता है लेकिन जब दो-तीन साल तक बरसात का पानी नहीं आता तो वहां पर क्या स्थिति

बनती होगी, इसकी कल्पना करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन इलाकों में पानी की समस्या पचास साल से है। आजादी के पचास साल बाद भी कई-कई मील दूर जाकर महिलाएं सिर पर पानी का एक घड़ा लेकर आती हैं। आज भी यह स्थिति पहले से बदतर हो गई है। जब पानी ही नहीं है तो घड़ा भरकर लाने का सवाल ही नहीं है। जब वहां पर चारा नहीं है तो पशुओं के जिंदा रहने का सवाल कहां है? हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है। मैं राजस्थान का निवासी हूं और मैं जानता हूं लेकिन मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पशु-धन एक बहुत बड़ी सम्पदा है, ग्रामीण समाज की। आज वह पशु सम्पदा इस हालत में है जिसकी कल्पना करना मुश्किल हो रहा है। वहां पर मृत पशुओं की संख्या कितनी है, इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं है। उनका पलायन भी हो चुका है, यह पलायन चरने के लिए नहीं बल्कि कटने के लिए हुआ है। गाड़ियों की गाड़ियां भरकर, कटने के लिए पशुओं को दूसरे प्रदेशों में लोग बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर अकाल की राहत प्रारम्भ कराने का दायित्व वहां की सरकार का है। वहां पर अक्तूबर से अकाल की विभीषिका चल रही है। अखबारों के जरिए वहां की जनता बराबर यह मांग कर रही है कि अकाल के लिए राहत कार्य आरम्भ किए जाएं। लेकिन महोदय, मैं आमतौर पर किसी सरकार पर आक्षेप नहीं करता। मैं किसी सरकार की आलोचना करके विषय को डायवर्ट नहीं करना चाहता। अभी माननीय भट्ट जी कह रहे थे, मैं अकाल की विभीषिका पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की पीड़ित मानवता अकाल से कराह रही है, इसकी ओर मैं ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते-दस दिन से मीडिया का ध्यान इस ओर गया है। मैं मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के अखबारों ने वहां के समाचार छापने आरम्भ किए कि वहां पर अकाल की स्थिति बड़ी भयंकर है। इससे दिल्ली में राजस्थान के अकाल की चिंता आरम्भ हुई और राज्य सरकार में भी हुई। मैं बड़े दुख के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जहां पर एक ओर अकाल की इतनी विभीषिका उस प्रांत में है, वहीं के हमारे राज करने वाले मुख्य मंत्री यह कहें कि हमारे यहां पर अकाल की स्थिति है जरूर लेकिन इतनी भयानक नहीं है, इतनी विकट नहीं है, इतनी खराब नहीं है। महोदय, यह ऑन दि रिकार्ड है और उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। एक तरफ प्रधान मंत्री जी सारे देश का आह्वान कर रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात तथा अन्य प्रान्तों में अकाल पड़ रहा है और जो एनजीओज हैं, अन्य लोग हैं या सार्वजनिक संस्थाएं हैं ....**(व्यवधान)**... .

**श्री मूलचन्द मीणा** (राजस्थान) : सर, ....**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अग्रवाल** : आपका नम्बर भी आएगा, मीणा साहब। आप भी राजस्थान

से हैं। ....**(व्यवधान)**...सर, मैं राजस्थान का एक प्रकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। ....**(व्यवधान)**...

**श्री मूलचन्द मीणा** : आपके सामने केन्द्र सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, आप उनको सुझाव दें कि वे ज्यादा से ज्यादा सहायता दें। ....**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अग्रवाल** : जब यहां से अपील जा रही है.तो मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के दानवीर सारे राजस्थान से बाहर हिन्दुस्तान भर में हैं और कई दानवीर तो हमारे इसी सदन में मौजूद हैं।

**श्री बालकवि बैरागी** (मध्यप्रदेश): एक दानवीर तो आप हैं ....**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अग्रवाल** : आप बोलेंगे तब मैं आपको सुनूंगा । ....**(व्यवधान)**...आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दानवीर कहा । हिन्दुस्तान के अंदर जहां-जहां भी संकट आया, राजस्थान के लोगों ने उड़ीसा में जाकर काम किया, लातूर में जाकर काम किया और गुजरात में जाकर भी काम किया था लेकिन वहां के लोगों को जानकारी मिलेगी, तब ही पता लगेगा कि वहां पर इतनी भयावह स्थिति है या इतनी विकट स्थिति है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुख्य मंत्री इस बात की अपील तक सारे देश में नहीं कर पाए कि आप आइए और कम से कम चारा तो भेजिए - और कुछ नहीं भेज सकते, दानवीरों के द्वारा पानी नहीं भेजा जा सकता । लेकिन पशुओं को बचाने के लिए, चारा भेजने के लिए तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के हमारे लोग, राजस्थान के प्रवासी इतना चारा भेज सकते हैं कि शायद मुख्य मंत्री भी उस चारे को नहीं पचा पाएंगे । चारा बहुत है - चाहे बिहार में कम हो गया होगा लेकिन चारा अभी भी बहुत है । इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक अपील निकाले - प्रधान मंत्री ने कहा है, उसका भी असर होगा और वहां के मुख्य मंत्री को भी चाहिएं कि वह हमारे दानवीरों से, वहां के उद्योगपतियों से इस बात की अपील करे कि चारा भेजा जाए । मैं समझता हूं कि चारा बहुत बड़ी मात्रा में आ सकता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि मैंने जो आपके सामने यह बात कही कि हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री या सरकार कान में तेल डालकर बैठी रही - यह मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, यह मेरे शब्द नहीं हैं, मैं एक आलोचक के नाते यह बात नहीं कह रहा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, आपने भी शायद पढ़ा होगा । कांग्रेस के अध्यक्ष ....**(व्यवधान)**...

**श्रीमती जमनादेवी बारूपाल** (राजस्थान) : आप आक्षेप मत लगाइए । वह बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर लिखना पढ़ना जानते हैं लेकिन हो हल्ला करना और

किसी सरकार के ऊपर छींटाकशी करना वह नहीं जानते ।

**श्री रामदास अग्रवाल** : महोदय, ये नई मेम्बर हैं इसलिए इनको चांस देना चाहिए । वह भी हमारे राजस्थान से चुनकर आयी हैं । अगर आप इनको बोलने का मौका देंगे तो अच्छा होगा । उपसभाध्यक्ष जी, मैंने जैसे कहा कि यह मेरे शब्द नहीं हैं । मैं अब इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या कर सकी है या नहीं कर सकी है । यह स्वयं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो हमारी लोक सभा की माननीय सदस्य भी हैं, अभी जब उनकी स्वयं की शायद पचासवीं या 51वीं वर्षगांठ जयपुर में मनायी गयी, उस समय जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने मुख्य मंत्री स्वयं भी बैठे थे, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य बैठे थे, उस समय उन्होंने, उस गिरिजा ने भवानी बनकर ललकार लगायी और सरकार को कहा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम असफल हो गये हो, तुम अकाल का सामना करने में एकदम गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे हो । यह बात उनकी अध्यक्षा ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में कहीं पर कोई कमी है तो हमारी राज्य सभा के कई सांसद यहां पर हैं, हम सब मिलकर उस सरकार के कान खींचें । उस सरकार के कानों को मरोड़ें । क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भी असफलता के कारण कोई आदमी मरे या पशु मरे। यह मानवीय पक्ष है, यह मानवीय पहलू है और इस मानवीय पहलू के ऊपर राजनीति से बात नहीं करनी चाहिए । मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ..**(व्यवधान)**..मैं नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह कहना चाहता हूं....**(समय की घंटी)**... - मैं कनक्लूड कर रहा हूं । इसे पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन सबने यह पढ़ा हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं और अभी हमारे माननीय सांसदों ने यहां कुछ बातें कहीं कि जैसे ही इस मामले के अंदर गंभीरता का प्रश्न बनने लगा तो केन्द्र सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है, और प्रधान मंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर - जो उनकी सीमा है, उससे भी आगे बढ़कर काम करने का प्रयास किया है ।

जैसे ही यह मामला गंभीर बनने लगा तो केंद्रीय सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की और प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर, जो सीमा उनकी है उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने काम करने का प्रयास किया। हमें प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने त्वरित गति से कार्यवाही की और तुरंत आगे कदम बढ़ाया । चाहे मुख्य मंत्री चेतें या न चेतें लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं इस काम में आगे आए । इस बारे में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, कल-परसों उन्होंने सारे देश का आह्वान किया है और इन इलाकों में अनाज भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है, पानी भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है ।

रेलवे को आदेश दिए गए हैं कि वहां पानी के फ्री वैगन्स भेजो, चारा फ्री भेजो । केंद्र सरकार जो कर सकती है वह उसे करना चाहिए । लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास धन नहीं है । यह स्पष्ट है और इस बारे में मुख्य मंत्री जी कई बार कह चुके हैं । उनकी कठिनाई क्या है यह मैं नहीं जानता । लेकिन उनके पास धन नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि धन की कमी से, साधनों के अभाव में, अनाज के अभाव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु राजस्थान में नहीं होनी चाहिए । वहां पर पशुओं की रक्षा होनी चाहिए और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे केंद्रीय सरकार करे, राज्य सरकार करे या दोनों मिलकर करें लेकिन अकाल का सामना करने के लिए हम सब को कुछ प्रयास करना पड़ेगा तभी जाकर हम अकाल की विभीषिका का सामना कर पायेंगे । आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से हम अकाल की विभीषिका के न दर्शन करा सकेंगे और न ही उसका समाधान कर पायेंगे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

SHRI M.P.A. SAMAD SAMADANI (Kerala): Thank you, Sir. I am here to make only a few suggestions to the Minister on this very important discussion. I would like to mention, very briefly, some points. As we all know, the serious drought situation has become a great threat in the day-to-day life of the people in certain States of the country, especially in Rajasthan and Gujarat. Food is scarce and drinking water has become a rare thing. The various dimensions of this problem have been discussed in detail. I am not going into those details and I am not repeating them. The most important problem is the non-availability of water. It is reported in the press that fights are taking place, among the people, in the villages, for drinking water. People are fighting each other for a drop of water and a serious situation has arisen in some of the areas. That is the most important aspect of this issue that has to be taken into consideration. A special relief package has been announced by the Central Government. The Secretaries of the Central Government are working on it. It is, no doubt, is a welcome feature. But that is not sufficient because the issue is very serious and grave. Because of that, something more is required to be done and some serious and urgent steps are to be taken by the Central Government to remedy the situation. I would like to give a few suggestions. Immediate monetary assistance, ample supply of foodgrains are the two important things, after drinking water. It is a very good news that the Railways have consented to free transportation of drinking water. This is a positive thing and the help from the Railways has to be

utilised to the maximum extent possible and more and more drinking water should be transported to all these areas. There is scarcity of foodgrains. For example, rice, it is reported, is a very rare commodity in those areas. Only the strengthening of the P.D.S can solve it. The PDS is, now-a-days, under threat. Only by strengthening this, we can solve the problem. Throughout the country, there is a problem with regard to the PDS. There is a need to strengthen this, especially in the drought-affected areas, for the use of the public. Also, the cleaning of wells is very important and the Central Government should make a system to scientifically clean all the wells that are there.

Now, Sir, I come to next point, that is, storing of water. Dr. Y. Radhakrishna Murty, during his speech, suggested the need for a balance between environmental awareness and development consciousness. Today, a fight is going on in the country between those people who argue for environmental awareness and those who argue for developmental activities. In fact, both, environmental awareness and developmental activities, are important. So, there has to be a balance between the two. A balance has to be found between the two, and more water has to be stored. It is reported that in the coming century, or maybe, in this century itself, the great battles among nations will not be for territories, but for drinking water. Thus, we are heading towards such a stage. It is a very serious problem, which humanity is facing. We will have to find out for the future as to what could be done. So much water is wasted nowadays. We will have to think of some kind of a scheme, some kind of a system, by which more water can be stored. Thank you, Sir.

**श्रीमती सरोज दुबे** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, गुजरात और राजस्थान भंयकर सूखे की चपेट में हैं। न सिर्फ इन्सान बल्कि जानवर भी पानी के लिए तड़प रहा है । कुएं, तालाब, नदियां और नाले सूख कर कीचड़ बन गये हैं । जब इन्सान ने कीचड़ पीने का सहारा लिया तो वह भी सूखना शुरु हो गये हैं । गुजरात में एक एक बाल्टी पानी के लिए मारपीट की नौबत आ गई है

यहां तक कि लोग जान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। जानवर मर रहे हैं, इन्सान तड़प रहा है । धरती का सीना बिलकुल चाक चाक हो गया है और किसानों की फसल बिलकुल सूख गई है । लेकिन अभी राहत का काम उतनी तेजी से शुरु नहीं हो

पाया जिसकी अभी तुरंत आवश्यकता थी । प्राकृतिक प्रकोप कोई नई बात नहीं है । प्रकृति का प्रकोप समय समय पर होता रहता है । कभी यह भयंकर तूफान के रूप में प्रकट होता है तो गांव के गांव उड़ा देता है। कभी बाढ़ के रूप में प्रकट होता है तो गांव के गांव बहा देता है। हज़ारों इन्सान और जानवरों को पानी की भेंट चढ़ जाना पड़ता है । कभी सूखे के रूप में जब यह प्रकोप होता है तो इन्सान को तड़पा देता है । आज भी सूखे का शिकार हमारे गुजरात और राजस्थान के प्रदेश हो रहे हैं । सूखे का प्रकोप पहले भी होता रहा है। इसीलिए हमारे यहां काले मेघ को खुश करने के लिए परंपरागत गीत बनाए गये । हमारी महिलाएं 'काले मेघ पानी दे' कह कर शाम को पूजा कर के आहवान किया करती थीं कि 'काले मेघ पानी दे'। इस तरह का आहवान होता था और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती थी। यह सूखे का प्रकोप कोई नई बात नहीं है । एक प्रत्याशित घटना है जिससे अगर सरकार चाहती तो बचा जा सकता था । लेकिन यहां तो इस तरह की कुछ स्वाभाविक आदत पड़ गई है कि विपदा सिर पर आ कर खड़ी हो जाए और गरीब इन्सान भूखा मरने लगे, इन्सान जब पानी के लिए तड़पने लगे, हजारों की संख्या में सूखे के कारण जानवर प्राण त्याग दें, उस समय सरकार को यह पता लगता है कि कहां सूखा पड़ गया । उसके बाद हो-हल्ला मचता है, हाय तौबा की जाती है तब आनन-फानन में जब कोई भी कार्यक्रम बनता है या कोई राहत का काम शुरु करता है । जब तक वह प्रक्रिया पूरी होती है तब तक सैंकड़ों जानवरों की जान चली जाती है और इन्सान अपना स्वास्थ्य भी गंवा देता है, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है । अभी कल हम लोगों ने देखा कि कुओं की यह हालत है कि लड़के-लड़कियां कुओं के अन्दर उतर कर जो कुओं में थोड़ा सा कीचड़ बच गया है, उस पानी को भरने का प्रयास कर रहे हैं । यह बहुत ही दयनीय स्थिति है । एक तो गर्मी का मौसम है और ऊपर से पानी की कमी है, ऐसी स्थिति में अगर राहत और सुविधा न पहुंचे तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है । हमारी राज्य सरकारें इस तरह की आपदाओं का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ हैं और केन्द्र सरकार की तरफ देखती हैं। यह प्रत्याशित घटना थी। पिछले कई सालों से गुजरात और राजस्थान में सूखे का प्रकोप चल रहा था। वर्षा बहुत कम हो रही थी । इस बार भी कई क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम हुई है इसलिए राजस्थान के करीब 26 जिले बिल्कुल सूखे के प्रकोप में हैं और उसी के कारण हजारों की संख्या में जानवर मर चुके हैं। अब किसान और निर्धन व्यक्ति जो हैं वे जानवरों को चारा नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उन्होंने जानवरों को छोड़ दिया है कि वे जहां कहीं चले जाएं और अपने जीवन की रक्षा करें।

महोदय, राज्य सरकारें आर्थिक दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं होतीं कि वे इस तरह

की आपदा का मुकाबला कर सकें। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार से 1,145 करोड़ की मांग की थी। लेकिन सरकार ने उसके बदले में उनको 103 करोड़ की सहायता प्रदान की है। इस समय भी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके बिल्कुल सूखे के प्रकोप के कारण तड़प रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की कटौती करना कोई बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है। अभी हमारे उस तरफ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूं और पूरा देश समझ रहा है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से सौतेला व्यवहार उन राज्यों के साथ कर रही है जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं। इस प्रकार मेरा यह सत्ता पक्ष के लोगों से अनुरोध है कि इस समय मानवीय आधार पर सहायता देनी चाहिए न कि इस समय पार्टी की बात को देखना चाहिए। राजस्थान के इन्सान भी उस प्रकोप से, भूख से और प्यास से तड़प रहे हैं। अकाल के कारण तड़प रहे हैं। वे भी इस देश के इन्सान हैं और गुजरात के लोग भी इसी देश के इन्सान हैं। इसलिए समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि इस देश के इन प्रांतों के लोगों को भी यह लगे कि हम भी हिंदुस्तान के वासी हैं और केंद्र सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है ..**(समय की घंटी)**

महोदय, अब जिस तरह से संकट बढ़ रहा है इससे यह लगता है कि आसपास के जिलों में भी - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश - इन जगहों में भी सूखे का संकट भारी होने वाला है। इसलिए पहले से इन जगहों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गुजरात में भी पानी का बहुत ज्यादा संकट आ चुका है। लेकिन पहले से अगर इंतजाम किया जाता तो शायद यह संकट कम हो सकता था क्योंकि वर्षा का कम होना अकाल और सूखे का उतना बड़ा कारण नहीं हो पाता जितना पानी का ठीक से इंतजाम न करना हो जाता है। गुजरात ने अपने राज्य के पानी के स्रोतों को बचाए रखने के लिए और उन्हें विकसित करने का कोई इंतजाम नहीं किया और जो कुछ पानी था उसे भारी औद्योगीकरण ने या तो इस्तेमाल कर लिया या प्रदूषित कर दिया। अपने सारे संसाधनों को सरकार ने सिर्फ नर्मदा योजना में झोंक दिया। स्थानीय स्तर पर पानी के इंतजाम करने में कोई रुचि नहीं दिखायी। उसी की परिणति यह है कि गुजरात में आज पानी का इतना बड़ा संकट हुआ है और इस तरह की तकलीफ उठानी पड़ रही है।

**एक माननीय सदस्य** : गुजरात में 1995 तक कांग्रेस की ही सरकार थी ..**(व्यवधान)**

**श्रीमती सरोज दुबे** : हां, मैं विशेष तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं। न

हम कांग्रेस सरकार की वकालत कर रहे हैं न आपकी आलोचना कर रहे हैं। हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि अगर गुजरात सरकार ने थोड़ी सी भी सतर्कता बरती होती तो आज शायद इतना भयंकर प्रकोप न हो पाता और आज जो त्राहि-त्राहि मची है शायद उससे गरीब जनता त्राण पा जाती। मेरे कहने का मतलब यही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

**श्री बालकवि बैरागी** : वे भूल रहे हैं कि राजस्थान में गए साल तक भाजपा की सरकार थी ..**(व्यवधान)** फिर क्या कहेंगे आप ...**(व्यवधान)**

**श्रीमती सरोज दुबे** : राजस्थान का हाल देख लीजिए वहां किस तरह की हालत हो गयी है ...**(व्यवधान)**... .

**श्री रामदास अग्रवाल** : उस समय केवल एक बार अकाल पड़ा था। दो साल में हमारे यहां राजस्थान में जब हमने राज्य किया तो केवल एक साल अकाल पड़ा था। आपकी सरकार आती है तब अकाल की शुरुआत होती है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : प्लीज, लेट हर कंप्लीट। लेट हर कंक्लूड।

**श्रीमती सरोज दुबे** : सूखा और बाढ़ हर साल आती है। लेकिन राहत के नाम पर थोड़े से अस्थायी इंतजाम किए जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि करोड़ों रुपया अस्थायी इंतजाम में लगा दिया जाता है और अगले साल फिर सूखे या बाढ़ का प्रकोप होता है तो फिर उस इंतजाम में पैसा खर्च किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसका स्थायी इंतजाम होना चाहिए क्योंकि प्रकृति का प्रकोप किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहेगा। जो सूखाप्रबल क्षेत्र हैं उनको सूखारहित क्षेत्र बनाने के लिए कई परियोजनाएं आयी थीं। और इस परियोजना की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री हनुमंत राव जी ने कुछ सुझाव दिए थे कि वाटर शैड परियोजना को ठीक से क्रियान्वित किया जाना चाहिए तथा नेशनल वाटर ग्रिड को मूल रूप दिया जाना चाहिए और पानी की जो समस्या है, पानी के जो हमारे स्रोत हैं, उनको पुनर्गठित किया जाना चाहिए, उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए । साथ ही साथ, पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए । हमारे यहां पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी की जाती है । इसलिए पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए । ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, उसको ऊंचा उठाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए ।

मैं एक शब्द और बोलूंगी । हमारे माननीय मंत्री प्रमोद महाजन जी ने कहा कि

मैं रेलगाड़ी भरकर पानी भेज दूंगा, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आप भेज देने की बात क्यों करते हैं, आप पानी भेज दीजिए और जितने भी सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां जितने गड्ढे हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उन सबको पानी से भर दीजिए ताकि जानवरों को पीने का पानी मिल जाए । साथ ही साथ, आपने जो 20 किलो अनाज देने का वायदा किया है, उसको आप 30 किलो कर दें । सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा और उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा जो कि जरूरतमंद लोग हैं । इसलिए इसकी निगरानी की जरूरत है । इसके ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी ताकि यह जो राहत सामग्री है वह उन लोगों तक पहुंचे । आपका जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है इस को आप सुधार लीजिए, नहीं तो यह सारा अनाज व्यर्थ ही चला जाएगा तथा गरीब और भूखा व्यक्ति उसी तरह से चिल्लाता रहेगा । इसके साथ ही साथ, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि इस समय वहां पर हर प्रकार की वसूली रोक दी जानी चाहिए तथा जनता और किसानों के बीच में राहत देने के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। जो बीमारी फैलने का खतरा हो गया है, लोग जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं, जो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, वे अब बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर बीमार हो जायेंगे, क्योंकि सूखे का प्रकोप अभी बहुत दिनों तक चलन वाला है, इसलिए बीमारियों से बचाने का भी अभी से आपको पूरा इंतजाम करना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि महामारी फैल जाए और तब आप इंतजाम करें । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को आपका यह निर्देश होना चाहिए कि वह तुरंत राहत कार्य प्रारंभ कर दे । केवल घोषणाओं में न रह जाए बल्कि जरूरतमंदों को तुरंत सुविधा व सहायता पहुंचनी चाहिए, ताकि सूखे के प्रकोप से, अकाल के प्रकोप से ये लोग पीड़ित न रह सकें। धन्यवाद ।

**श्री अहमद पटेल** (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । सत्र के पहले ही दिन, गुजरात में सूखे की स्थिति के बारे में मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था । इससे पहले भी इसी सदन में सूखे के बारे में, बाढ़ के बारे में, कभी अर्थक्वेक के बारे में, कभी साइक्लोन के बारे में, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती रही हैं । लेकिन ये चर्चाएं कब तक होती रहेंगी, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, उसका इलाज़ क्या है ? आज हम हाइटैक की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं । जब भी कोई ऐसी विपदा होती है तो हमेशा यह मांग आती है कि इसको नेशनल कैलामिटी, राष्ट्रीय विपदा घोषित करना चाहिए । जब यह बात उठती है तो ज्यादा फाइनांशेल असिस्टेंस की बात उठती है । सैन्टर के पास जब

**6.00 P.M.**

पैसे नहीं होते हैं तब यह नेशनल कैलामिटी की परिभाषा की बात होती है । उड़ीसा में भी यही बात हुई या जहां पर भी पहले विपदा आई, ऐसी बात हुई है । मैं समझता हूं कि सारी पोलिटीकल पार्टीज़ को इस पर बैठकर सोचना चाहिए और कोई ऐसा कोष बनाना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी विपदा आए तथा राज्य सरकार अगर आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उसमें से उसकी मदद की जाए । जब भी कभी ऐसा होता है तो मुख्य मंत्री जी मेमोरेंडम लेकर आ जाते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ के लिए । मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा और कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि आने वाले दिनों में बार-बार हमको इस विषय पर बहस न करनी पड़े । जहां तक गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों का सवाल है, मैं समझता हूं कि वहां स्थिति बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और भयावह है और सब से ज्यादा, मैं यह नहीं कहूंगा कि अन्य प्रदेशों में नहीं होगी .....।

लेकिन मैं समझता हूं कि गुजरात की स्थिति ज्यादा ही चिंताजनक है । महोदय, मैं यहां कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि गुजरात के सत्ता पक्ष के मेरे साथी सहमत होंगे, हो सकता है यहां मेरी बात का समर्थन न करें, लेकिन बाहर जरूर सहमत होंगे कि गुजरात की क्राइसिस को जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है । यह बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि टाइमली जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, वह नहीं हुआ । अभी ब्रह्म कुमार जी बता रहे थे कि अखबारों द्वारा लिखे जाने पर सीरियसनेस आई । मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस क्राइसिस को उठाया और जिस की वजह से राज्य सरकार और केन्द्र की सरकार जाग्रत हुई। उपसभाध्यक्ष जी, क्या यह बात सही नहीं है कि गुजरात में मानसून फेल हुआ या जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसको एंटिसिपेट करके जिस तरह से कंटेंजेंसी प्लान बनना चाहिए था, जिस तरह टाइमली केन्द्र सरकार को मेमोरेंडम सबमिट करना चाहिए था, वह नहीं किया गया ? क्या यह बात सही नहीं है कि मुख्य मंत्री को अमेरिका जाने के बजाय दिल्ली आकर अपने इंफ्लुएंस का कृषि मंत्री या प्रधान मंत्री पर उपयोग करना चाहिए था ? मुझे नहीं मालूम कि उन्हें वहां क्या काम था और मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं । क्या यह बात सही नहीं है कि प्रधान मंत्री जी जब गुजरात गए तो यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उनको एफेक्टेड एरिया की विजिट कराते जिससे गुजरात को फायदा होता ? उपसभाध्यक्ष जी, यह पहली क्राइसिस नहीं है, इससे पहले भी कांडला में साइक्लोन आया जिस में 17 सौ

लोग मारे गए और जिस तरह से उस क्राइसिस को मैनेज करना चाहिए था, वह नहीं किया गया । सूरत में बाढ़ आई और उकाई के डैम का पानी जिस तरह से इंस्टालमेंटवाइज छोड़ना चाहिए था, वह नहीं छोड़ा गया । उस कारण जब बारिस आई तो फ्लड हो गया और लोगों का काफी नुकसान हुआ । तो क्राइसिस जिस तरह से मैनेज होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई । यह हकीकत है और इसे स्वीकार करना चाहिए । उपसभाध्यक्ष जी, इस बारे में और कोई अखबार ने नहीं बल्कि 'पायोनियर' ने लिखा कि :

Gujarat: Not to manage a crisis. It is a serious crisis.

जो हकीकत है, उसे स्वीकार करना चाहिए और इस समस्या का हम सबको मिलकर हल निकालना चाहिए । इसके लिए हमारे सामने बैठे साथियों को हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं । अगर आवश्यकता हो तो हम प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाने के लिए तैयार हैं ।

गुजरात भवन में जो मीटिंग हुई थी । मेरे साथी सहमत होंगे कि मैं ने कैटल्स मारे जाने का मुद्दा रेज किया था । उस पर मुख्य मंत्री जी का जवाब आप अच्छी तरह से जानते हैं । जवाब था कि जो कैटल्स मर रहे हैं, वह राजस्थान से आ रहे हैं । मुझे मालूम है कि अग्रवाल जी को इस विषय पर क्या कहना है । चूंकि वहां सब्सिडी कम है और गुजरात में ज्यादा है, इसलिए वहां के कैटल्स गुजरात के बॉर्डर पर आकर मर जाते हैं । It is very ridiculous. उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह की चिंताजनक और भयावह स्थिति वहां है । वहां बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए पानी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता । अभी हमारी बहन जी बता रही थीं कि कुएं में रस्सी बांधकर या साइकिल के टायर पर बिठाकर महिला को कुएं में उतारकर पानी निकाला जाता है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है ।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए वर्तमान सरकार दोषी है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात आई थी । वह जितनी जल्दी खत्म होना चाहिए था, नहीं हो पाया। हो सकता है उस में सभी की गलती हो, लेकिन अब तो गुजरात में आप की सरकार है । मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है। पटवा जी यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि ट्रिब्युनल ने जो अवार्ड दिया है, जो हाइट तय की है, अगर वह हाउस में एश्योर कर दें कि वह हाइट मुझे मंजूर है, मध्य प्रदेश के लोगों को मंजूर है तो मैं मुख्य मंत्री पर दबाव डालने के लिए तैयार हूं । लेकिन यह डबल स्टेंडर्ड की बात नहीं चलेगी कि मध्य प्रदेश में कुछ बात करेंगे और गुजरात में कुछ और बात करेंगे । यह ठीक नहीं है। उनकी भी सरकार थी, वह भी मुख्य मंत्री थे तब वह सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए । प्रधान मंत्री जी भी गुजरात गए थे और तीन वायदे करके आए थे । उन्होंने कहा था कि

कावेरी का इश्यू जिस तरह से हमने सॉल्व किया है, उसी तरह से सरदार सरोवर का इश्यू भी सॉल्व करेंगे । वहां वह मुख्य मंत्रियों को बिठा सकते हैं तो अब चुनाव हुए भी काफी टाइम हो गया और हमने प्रधान मंत्री जी को याद भी दिलाया कि अब तो आप के हाथ की बात है । बिठाइए, हम अपने मुख्य मंत्री पर दबाव डालेंगे ।

उपसभाध्यक्ष जी, गुजरात में पीने के पानी या कृषि के लिए पानी का जो प्रॉब्लम है, उसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वह सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है । मध्य प्रदेश के लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे । महोदय, सन् 1986-87 में जब ड्राउट आया था और वहां हमारी सरकार थी तो वहां राजीव गांधी ने तीन-तीन बार दौरा किया था । सेंटर से हमें पूरी फायनेंसियल असिस्टेंस मिली थी, ट्रेन में पानी भेजा गया था, फॉडर भेजा गया था और जिस प्रकार से उस ड्राउट सिचुएशन को हेंडल किया आज उसी प्रकार से करने की जरूरत है । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपील की, उन्होंने पीने के पानी के लिए ट्रेन देने की बात की है, 20 किलो राशन का अनाज देने की बात की है, आई ऐप्रिसिएट देम, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस काम में जल्दी करने की जरूरत है, सिचुएशन खराब हो जाए उससे पहले कुछ करने की जरूरत है और अगर हम सब लोग मिलकर सोचेंगे, दबाव डालेंगे तभी यह हो पाएगा । रिलीफ वर्क चल रहे हैं लेकिन जिस मात्रा में चलने चाहिए, उस मात्रा में नहीं चल रहे हैं । हो सकता है कि सरकार के पास अधिक राशि न हो, धन न हो इसलिए जिस मात्रा में, जिस परिमाण में रिलीफ वर्क होने चाहिए, उस मात्रा में वे शुरू नहीं हुए हैं । रिलीफ वर्क में भी कह रहे हैं कि 40 रुपए मिल रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस बारे में भी काफी जगह से शिकायतें हैं, कम्प्लेंट्स हैं । जो परिवार सुबह से लेकर रात तक काम करता है उसमें किसी को 10 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 15 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 20 रुपए मिल रहे हैं और वहां भी करप्शन चला हुआ है - जो वीकली पैसा मिलना चाहिए, मेज़रमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और दो-दो, तीन-तीन वीक तक मेज़रमेंट नहीं होते । वहां पर शैल्टर नहीं हैं, मेडिकल असिस्टेंस जिस तरह से वहां पर काम करने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है । ये सारी चीजें हैं और इनके बारे में हमें मिल-जुलकर सोचना होगा, प्रयास करना होगा । भूख की वजह से वहां 2 व्यक्तियों की जान चली गई, वहीं पर काम कर रहे थे । ऑन दि स्पॉट, वहीं घंटे बाद धूल में, मिट्टी में उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक दाना भी नहीं था अनाज का और ऐक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये टी.बी. की वजह से मारे गए । जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए । तो वहां रिलीफ वर्क ज्यादा से ज्यादा खोलने



18—160/RS/ND/2000

चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि लोगों को कम से कम मिनिमम् वेजिस तो मिल सके, 40 रुपए तक तो कम से कम मिले, जो पूरे परिवार के साथ धूप में काम करता है उसे कम से कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए । जहां तक पीने के पानी का सवाल है, उसके बारे में बहन जी ने बात की है और मैं समझता हूं कि उसका जल्द से जल्द प्रबंध किया जाना चाहिए । जहां तक फोड्डर का सवाल है, अगर पहले से एंटिसिपेट किया होता तो आज यह स्थिति न होती । शूगर फैक्ट्रीज़ से और बाकी लोगों से बात की गई, लेकिन थोड़ी लेट की गई, कुछ लोगों को इंसेंटिव देकर अगर वहां पर कहा होता कि आप चारा उगाइए तो स्थिति संभल सकती थी, लेकिन वह नहीं हो पाया और यह हकीकत है । अभी भी वहां पर जितना स्टॉक होना चाहिए, वह नहीं है । पीने का पानी, रिलीफ वर्क, फोड्डर, इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना होगा और मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको मिल-जुलकर सहयोग करना होगा, सबको मिलकर प्रयास करना होगा ताकि एस.एस.पी. प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, उसका कुछ सॉल्यूशन निकले । वेंकैया नायडु जी से भी मैं कहूंगा कि वे अपने इन्फ्ल्युएंस का यूज़ करें प्रधान मंत्री जी पर कि कम से कम वे इसका कुछ हल निकालें । मही नदी से जो पानी लाने की योजना थी, उस बारे में कहा गया कि कांग्रेस के काल में कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 150 करोड़ रुपए रखे गए थे लेकिन जब बी.जे.पी. की सरकार आई वहां पर तो उस बजट को 150 करोड़ से 4 करोड़ कर दिया गया । वह अल्टरनेटिव स्कीग थी और उससे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती थी लेकिन वह भी नहीं हो पाई । हमें कुछ अल्टरनेटिव स्कीम सोचनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए । 900 करोड़ रुपए का प्लान था, 1100 करोड़ रुपए का हुआ, फिर 55 करोड़ रुपए मिले । तो और ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले पी.डी.एस. सिस्टम में, खास तौर पर जो मज़दूर वहां रिलीफ वर्क पर काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हैं, जिन पर हमें मिल-जुलकर काम करना चाहिए और जैसा मैंने शुरू में कहा कि बजाए इसके कि बार-बार हम इस पर चर्चा करें, हमें कोई ऐसा हल निकालना चाहिए ताकि हमें चर्चा ही न करनी पड़े । धन्यवाद ।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with Shri Ahmed Patelji that political parties should all sit together, come together, to evolve some sort of a solution to this sort of problem, whether it is cyclone, whether it is drought or any other natural calamity, for that matter, in any part of the country. There has to be a proper approach; and there has to be co-ordination between the Central Government and the State Governments.

Sir, before I go to that issue, I have taken the permission to mention about the situation prevailing in parts of Karnataka. Twenty-one districts of Karnataka are also facing a drought situation, particularly, the border areas Kolar, Bellary, Raichur, Bidar, Gulbarga, Bhagalkot, Belgaum, Kaveri, Chitradurg, Tumkur and Davangere which are adjacent to Andhra Pradesh, are facing a grave situation. In Andhra Pradesh also, out of 1103 mandals, 743 mandals have already been declared by the State Government as drought-affected areas. There is migration of labour. There is a severe drinking water shortage. There is a shortage of fodder. These are the main important things. I am happy that the Government of India has announced that they are ready to provide foodgrains that are required by the affected States. They have also decided to provide free transportation of the fodder and also drinking water to the affected areas.

I am also happy that the Prime Minister has called a meeting at 6 o'clock today to take the suggestion of different political parties. All should evolve a consensus approach to tackle this problem. Sir, I wanted to rise, in fact, a wider issue. Manmohanji and Jaswantji and others are not here because they are pre-occupied with the meeting called by the Prime Minister. Ahmed Patelji was referring to the States asking for funds. I have gone through this. Rs.700-odd crores are asked for by Gujarat, Rs.1100 crores are asked for by Rajasthan and Madhya Pradesh also has asked for a similar amount. Then we have a memorandum from Karnataka also. Andhra has asked for Rs.650 crores. If you put all these things together, what will happen? Simply because we are at the Centre today, I am not trying to put an accusing finger against any State Government. Fortunately or unfortunately, most of the States are ruled by different parties. We are hearing here in this House, people trying to find fault with State Governments. People try to find fault with Gujarat. My people try to find fault with Rajasthan. Somebody else tries to find fault with Andhra Pradesh. We are not serving the cause of anybody by doing this. I do not want to go into the details. I also have information. I also have newspaper reports. Today, one of the newspapers said: "This should be an eye-opener to all of us. It seems the State Government has chosen to take two separate stands-one to highlight the severity of famine when it comes to taking assistance from the Centre and the second to term reports on droughts as 'media hype' when it comes to exposure of the administrative failure to provide drinking water, fodder, to the drought-hit villages. A senior official of the Chief Minister's Office denied any

information of cattle death or even migration of people from the drought-hit districts." How irresponsible it is! I do not think that any politician can make such a statement. I am not attributing it to the Chief Minister of Rajasthan. I do not want to join issue on that. I am talking about the issue involved. We should really take note of it. I am not mentioning the name of the Chief Minister. It does not concern the Chief Minister as such. I am talking about the administration. Political parties should take note of this attitude. "All this is a routine affair. There is nothing very special this year." An officer speaks like this! Members are saying that there is a serious situation, there is migration of people, there is shortage of fodder, there is cattle death. According to newspaper reports, about 50 cattle have died in every drought-hit village in Rajasthan. The same will be the case in Gujarat, the same will be the case in Andhra Prdesh, if it continues like this. This will happen. That being the case, we should evolve a solution. You have laid down certain guidelines with regard to the National Calamity Relief Fund. This is not made by the BJP Government or the Congress Government. Even if Communists come to power tomorrow, they will have to follow this. You must evolve a system where whenever such a situation arises in any part of the country, the Centre and the State together should take the responsibility. There is no politics involved in this. Somebody was trying to misinterpret what Patwaji has said. Patwaji has said that basically this work has to be executed by the State Governments. Even if the Centre gives Rs.1000 crores as required by Rajasthan or Rs.700-odd crores as required by Gujarat, the Centre cannot go there and open fodder depots and also cannot distribute drinking water by itself. It will be an encroachment into the responsibilities and functions and rights and duties of the State Government. The Centre has to supplement, has to augment, the efforts that are being made by the State Government. Some people forget the responsibility. They are saying सेंटर को पहले ही मालूम है, उन्होंने कुछ किया नहीं ।

I am not one to agree with them because I am not willing to blame either the Centre or the State. It is nature's fury. It is a natural calamity. We are in the beginning of the calamity, Sir. I would like to caution, we are yet to pass May-June. A very difficult situation is ahead of us, particularly, with regard to drinking water, particularly with regard to fodder, because when there are no rains, there is no question of fodder being available anywhere. You have to take it from other States. You have to transport it. There is news in the newspaper today saying that Rajasthan has opened fodder depots.

But people are not in a position to purchase it because they do not have money. It is a practical problem. The same may be the case in Gujarat also. So, you have to supply fodder either free of cost or at a subsidized rate. This issue has to be kept in mind. As far as drinking water is concerned, whatever may be the cost of it, the Centre and the State should bear it and supply water.

The hon. Member, Shri Brahmakumar Bhatt has made a suggestion. I went to Rajkot some fifteen, twenty days back. There is a drinking water problem. The drinking water is supplied only for few hours or it might have come down also. But if we are trying to find fault with somebody and then trying to make a political allegation against a political party or a Government, that will not solve the problem.

As far as the issues of politics are concerned, we have wider oppportunities to discuss them and debate them. Sir, what is the situation today? Today, I was there in the briefing. I want to share my experience with my friends here. The media men were asking as to what this drought is. Is it serious? I said: "It is serious." They said that seriousness is not reflected in the Lok Sabha. Out of 543 people, there were hardly fifty Members. Today also, I find the same situation in our House. It is a reflection. So, that being the case, we should take it seriously, in a proper perspective and then do proper introspection and come with a realistic solution and also realistic demand. I was raising this issue about States' demand. Whose money is this? After all, this is people's money only.

Coming back to the main issue, my suggestion is that the States should give a realistic assessment of their requirement. The Centre and the States together, if necessary, can discuss this in the Chief Ministers conference or the National Development Council and formulate a new policy. We find that there is no money in the National Calamity Relief Fund. Andhra has seen some problem. Orissa also have seen some problem. There is a demand to declare it a national calamity. Similar demands will come from other States also if the situation continues like this. That being the case, there has to be a proper approach and consensus among all political parties with regard to distribution of these funds and mobilisation of resources. We may have to think in terms of mobilising additional resources for this purpose. Otherwise, what is the way out? You have Rs. 1,24,000 crores debt service, you have problems in the Oil Pool Account, you have problems in other accounts. But, at the same time, you cannot allow the people to die, you cannot allow the people to suffer without drinking water, you cannot allow cattle to die and

the cattle wealth to deplete like this which have already depleted because of various reasons. You cannot allow them to get further depleted. That being the case, some constructive and meaningful suggestions will emerge from today's all-party meeting. I only appeal to all political parties to take a constructive approach on this and then come to a conclusion with regard to pooling of resources and also with regard to distribution of resources. I was really pained when I found our friend, Balkavi Bairagiji also, sitting in front of the Parliament today. Sir, somehow, I am not that much matured and senior to understand all these things. We have a forum here, Parliament. We are here to discuss the issue. It has become a practice with the political parties to stage dharnas in front of Parliament. Tomorrow, my party will do it, day after tomorrow, somebody else will do it. Are we in a position to convey a proper message to the general public through the Parliament? We have a forum here to discuss. You are kind enough to allow. The rule says that only one Member from one party. But today, the Chairman was kind enough to allow a number of Members because people from Kutch district, people from Banaskanta, the local people, will ask them as to what they have done. They have not even raised the issue. So, that being the case, let us utilise this forum to discuss this issue and then come to some conclusion and have a constructive and meaningful solution to this problem rather than making politics out of the present situation. I do not want to take further time of the House. My priority is to give water, my priority is to make available fodder to the cattle, my priority is providing work to the people. "Food for Work Programme" is a good programme. Fortunately, we have enough foodgrains, sufficient not only for this year but also for the next year. That being the case, the Central Government should have a liberal attitude with regard to the supply of foodgrains to the affected areas and these foodgrains should be distributed to those people. Earlier, they used to engage themselves in agricultural activities. Now, there is no activity left because there is no water. So, there is no question of cultivation or anything like that. That being the case, these things have to be provided to them. These minimum things will go a long way in mitigating their sufferings. In addition to this, the State Governments should mobilise resources to meet the situation. Thank you.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Sir, Rajasthan and Gujarat, as also parts of Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, are severely affected by drought. The people of

Rajasthan and Gujarat are starving for days together. They go miles together to fetch one pot of drinking water. Their cattle, camels and other livestock are diminishing day by day because of lack of water and they are dying before their masters' eyes. Our own brethren in these States are suffering due to unprecedented drought in that area. It is reported in the Press that for the last ten days, 26 of the 32 districts of Rajasthan are in the grip of a severe famine. People are migrating and there is no drinking water in large parts of the State. The fair price shops have only kerosene and sugar and there are no foodgrains. Gujarat is facing severe drought conditions for the last hundred years. More than 143 dams and reservoirs in Saurashtra, Kutch and North Gujarat have already dried up. Others have water for a fortnight only. I am of the firm conviction that we have to take long-term measures to solve the drought and famine problem.

We have faced drought and famine situations on so many previous occasions. But it is a question of timely planning. We must have a long drawn plan to avoid repetition of such kind of things in future. The Central Government and the State Governments should make every possible effort to save the lives of the people and get over the difficulties. So, we have to help them in this hour of crisis. Relief work has to be extended to these areas as quickly as possible. The Central Government has to protect the interest of the people and extend a helping hand to them. Our hon. Prime Minister appealed to the people of the country to contribute their lot for this cause. We all join with him and I am confident that our Prime Minister and this Government will get over the situation.

In this connection, I wish to urge upon the Government to have a long-term plan to face any such calamity in future. Every year we face drought either in the Southern, Northern, Western, or, Eastern parts of the country. Failure of the monsoon and delayed rains are the factors which cause this calamity. Last year, we faced the worst experience of a super-cyclone in Orissa. The coastal areas of Orissa are very much affected by cyclone. But the report says that this year that part is affected by drought. Those parts have turned into drought-prone areas. Due to the cyclone, all the trees have been uprooted and that area is now looking like a desert. Due to this, the rainfall which was due this year has not occured. The failure of the monsoon is due to the havoc created by the human society. There is widespread deforestation and the use of all kinds of machines has polluted our environment. These are the reasons for the failure of the monsoon.

So, we have to take all these things into account and plan accordingly to avoid such calamities in future. Our national plans with regard to this should be implemented. We have to plan schemes and we have to implement them without any fear or favour. We have to harness the rain water during the monsoon and save it by constructing proper dams and check-dams and by storing in big tanks and ponds. We have to link all the rivers of India. We are told that in Rajasthan people have to walk miles together to get a pot of water. If we link all the rivers, we can divert the water to where we want. In some areas we are facing drought and, at the same time, in some areas we are facing flood. So, there has to be some kind of a plan for future. In this context, I wish to bring to the notice of the Government that when Mr. K.L. Rao was the Minister of Irrigation, he advocated a policy of linking all the rivers under the caption "River Garlanding Scheme". This had not been examined properly and I think it had been dropped. I request the hon. Prime Minister and this Government to explore that possibility and try to bring out a full-fledged scheme to avoid this kind of calamities in future. With these words, I conclude and thank you.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA (Andhra Pradesh): Sir, we are all aware of the serious situation of drought in some parts of India and today we are all showing our concerns for the affected States. I am really happy, and thankful to our hon. Prime Minister, that he is showing some concern for the States, including Andhra Pradesh. The Government of India has arranged the machinery to prevent such situations. But nothing worked and it had all failed. Every year we are facing either drought or flood. There is no permanent remedy to safefugard the victims when such a situation arises. The People of Gujarat, Rajasthan, Orissa and Andhra Pradesh are fighting for a drop of water to drink to live. In Rajasthan farmers are putting the tilak to the cattle and saying "al-vida" because they know very well that they will not be able to look after them and save them when they are not able to save themselves. It is a very sad situation that we are facing. I appeal to everybody and the Government to come forward and help the affected people. The Government is not providing water to the people and fodder to the cattle. The relief operations are inadequate and inefficient. In this context, I would like to draw the attention of the Government to Andhra Pradesh-I belong to Andhra Pradesh--where we are facing the serious problem of drought. In Andhra Pradesh 688 mandals in 18 districts like Telengana, Rayalaseema, Mahaboobnagar, Warangal, Medak, Ranga Reddy, Ananthapur, Chittore and

Cuddapah are affected adversely due to rain deficiency. The crops have been damaged due to a long dry-spell. There is hardly any yield, particularly, in Mahabubnagar. And if you look at the Telangana area, you will find that almost 90% of the crop has been damaged. This is a very serious problem, so far as Andhra Pradesh is concerned. The farmers are committing suicide and there is no water to drink. Last year, the Government set up a committee which has failed to tide over this natural calamity and hardly helped the State during this hour of crisis. The committee did not even make any effort to tackle the present situation. Sir, with your permission, I want to mention- and you must be knowing it - how, last year, our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu, had helped the super-cyclone victims in Orissa. The whole world was appreciative of his gesture and of the steps which he took when Orissa was caught under the grip of a super-cyclone. Sir, today, in Andhra Pradesh, we are also facing the same situation. The State of Andhra Pradesh has been severely affected by this drought. We have made so many appeals to the Central Government. The State Government of Andhra Pradesh is trying its best to provide relief. The Chief Minister has taken so many steps after visiting the drought-affected areas, such as rescheduling of the crop loans, sanctioning of fresh loans, etc. The crops have been damaged and the farmers are committing suicide. On top of it, I have got information that the nationalised banks are pressurising the farmers to pay back the loans, despite knowing the condition of the farmers. Sir, I would say, this kind of harassment should be stopped immediately so that the farmers could be saved from this kind of harassment. One more thing I would like to tell you is, the agricultural situation in Andhra Pradesh is very bad. This sector has been badly hit by drought. But still Sir, the women, if you look at Rajasthan, go with their pots in the morning and come back to their houses only in the evening. Because that place is very far from their houses. मैं एक एक्ज़ाम्पल बताना चाहती हूं । आज के पेपर में आया है कि एक आदमी गधे के ऊपर पॉट रखकर पानी लेने गया । जब मालिक पानी लेने गया तो उसको पानी लाने में इतनी देर हो गई कि उस गधे ने अपने मालिक का इंतज़ार करते-करते अपने आप को खत्म कर लिया । This is the kind of situation which is prevailing there. This is not an exaggeration. It is the real situation. We are facing it. In view of this, I request the Central Government and the State Government to join together and take immediate action in this regard. When something happens, we think about it. When floods take place, we think about that. When drought takes place, we think about that. We do not foresee and take a long-term view. I

only request that preventive action must be taken so that the lives of the poor and the downtrodden, who are suffering for want of water, and the cattle which is suffering for want of fodder, could be saved. I request this Government to react to the situation. Thank you for giving me this opportunity.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, the situation is very bad all over the country due to drought conditions. In Gujarat 17 districts and 153 Talukas have been affected. In Madhya Pradesh 7 districts are affected. In Rajasthan 26 districts are affected. Some districts have been affected in Andhra Pradesh. In Orissa also many districts have been affected. The situation in Orissa is very serious because the people of Orissa first witnessed cyclone and then floods and now they are facing drought conditions with heat wave also. Sir, you might have read in the newspapers day before yesterday that in Kitlagarh area of KBK districts, the temperature was 47 degree Celsius. In the coastal area of Bhubaneswar it was 42 degrees Celsius. We apprehend that the temperature may go up beyond 50 degrees Celsius in future. In the last cyclone in Orissa, 12 districts and around 125 blocks were affected, 10,000 people died, 25 lakhs of houses were damaged and 35 lakhs of cattle were killed. Now the rest of the 18 districts which are in the western part of Orissa like Koraput, Malkangiri, Sambalpur, Sundargarh, Kalahandi, Rayagada, Joypore, Bolangir, Deogarh, Dhenkanal, Phulbani, Ganjam, Gajapati, Jharsuguda, etc. are the worst affected districts. The heat wave is also going up day by day. In this situation, as I have said, the Central Government has given some funds to the KBK districts. The State Government has also done some work. But it seems that it is of no use because even drinking water is not available in these districts. The State Government has levelled an allegation that the Central Government has not given funds. The Central Government is saying that they have given enough funds for making available drinking water and for constructing roads, etc. The situation in Orissa is very precarious. The State Government is saying that they don't have any funds. Sir, as I mentioned earlier, the people of Orissa have not still recovered from the shocks of cyclone and floods.

Now they are facing the drought conditions. Now the main problem is of drinking water. As I said earlier, after the cyclone in Orissa, 10,000 people died. Till today only 2000 families have got ex-gratia amount. The rest of

the 8,000 families have not got any help. The hon. Minister clearly stated in this House that 2, 50,000 houses would be given under the Indira Awas Yojana. But only 15,000 houses have been given. Those houses also could not be distributed. I am sure that not a single house would be constructed before the monsoon. Even the roads which had been damaged have not been reconstructed till date. I don't blame this Government or that Government. One Government goes and another Government comes. This is a continuous process. The other day some people said, "Your Government could not do it." I do agree. Our Government could not do it. That is why the people have rejected them. The people of Orissa are in a miserable condition.

As my friends have said, we may see a famine-like situation in Orissa. Millions of people may die in future. Sir, there is no drinking water. There are no houses. You can imagine what would happen after one month or so when the monsoon starts. Again there will be rain. Nearly 25 lakh families will have to stay under the open sky. The whole crop has been damaged in the State. A part of the crop was damaged by the cyclone and floods and the rest of the crop is damaged by the drought conditions. This is the situation in Orissa. I don't blame anybody. But the situation in Orissa is very, very precarious. I agree with my brother, Mr. Naidu, and others, who have also given the suggestion that the Central Government and the respective State Governments should sit together and review the situation; if required, the hon. Prime Minister should also call a meeting with the Governments of the States where the drought situation, the flood situation and the cyclone siutation is very serious. This should be discussed immediately. Otherwise, we must have a joint parliamentary committee to visit these States, see the situation and suggest what can be done. Sir, we know the situation prevailing in Orissa. In many places, there is no drinking water. Thousands of villages have gone without water. The same is the case in Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Gujarat. Knowing well that there is no drinking water, is it not the duty of the State Governments or the Central Government to find out a way to solve this problem in future? We must be careful and see to it that there is no shortage of drinking water the next year. But we do not foresee things. There is no scheme whatsoever. We do not have any plan. Even if we have a plan, the bureaucrats never implement it. Take the case of the reliefs being supplied by various people. We are very much obliged to the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh -- Mrs. Jayaprada Nahata and the other hon. Members also mentioned it -- for helping us in this time of crisis.

Apart from various State Governments, the NGOs and other organisations are also providing relief materials to the State. We are very much obliged to them. Even the Prime Minister visited the State. Our leader, Smt. Sonia Gandhi, visited the State. And, as per the instruction of Soniaji, the Chief Minister of Goa has adopted certain districts, and the work is also going on. We are obliged to him. But the fact remains that in spite of all this help, the relief materials which have been supplied to the State have not been unloaded till today. One hundred and forty seven wagons with relief materials are yet to be transported. The monies which have been given by various State Governments could not be utilised till today. The assistance being provided by NGOs and various other organisations have not been utilised. For this, we have to gear up the machinery and the administration, and we have to make them work. It is only then that the relief materials can reach the people of the drought-prone and the cyclone-affected areas. Another thing which I want to mention here is that around 10 lakhs of people of Orissa are working elsehwere. And, the people there are not getting fodder also. Thirty to forty lakhs of people have left their villages, and they are going in search of work elsewhere. So, this is the situation. It is only when the work under the various schemes like the Indira Awas Yojana really get started in these States, can the people get some relief. I urge upon the Government to reivew the situation, and also to appoint a joint parliamentary committee which can visit the affected places, review the situation and recommend necessary remedies to face the situation. Thank you, Sir.

**डॉ. स्वामी साक्षी जी महाराज** (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया सर्वप्रथम उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा के कारण देश में तबाही मच जाती है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूखे के कारण अकाल की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है । माननीय सदस्यों के माध्यम से, समाचार-पत्रों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है परंतु मुझे लगता है कि सारे मामले में न तो सरकार की नीति ठीक है और न ही नीयत ठीक है । राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलौत जी ने प्रधानमंत्री के सामने दिनांक 16-11-99 को प्रस्तुत होकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी और यह कहा था कि बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है । आज से पांच महीने पहले एक प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने उपस्थित होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और वह 1145 करोड़ रुपया समस्या के समाधान के लिए मांगता है और सरकार उस पर गौर नहीं फरमाती, ध्यान नहीं देती है । बड़ी मुश्किल से 102

करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाते हैं । केवल स्वीकृत किए जाते हैं अभी दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं पता नहीं है । स्थिति बड़ी भयकंर है और मुझे आश्चर्य होता है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो एक बहुत संवेदनशील मामला है उसको राजनैतिक रूप देना चाहते हैं । ऐसे मामलों को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए । लेकिन यहां भी कह रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, लोक सभा में जसवंत सिंह जी के साथ कांग्रेस के सदस्यों की नोंकझोंक भी हो गई । कुछ मामले ऐसे हैं जिनको राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए । मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं । 5 अप्रैल को जनसत्ता में एक समाचार है कि जयपुर में एक मीटिंग हुई । उपसंभाध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे मित्र ललित किशोर चतुर्वेदी ने की और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पूरे के पूरे राजस्थान में संघर्ष समितियां बनायेंगे और हम वहां की सरकार के खिलाफ जेहाद छेड़ेंगे, इस सरकार का हम विरोध करेंगे । हम गांव गांव में निकलेंगे, हम जिले जिले में जायेंगे । क्या यह राजनीति नहीं है ? अगर नीयत ठीक होती, अगर नीति ठीक होती तो उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए था कि जो लोग भूखे हैं उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, जो प्यासे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे और पशुओं के लिए हम चारे की व्यवस्था करेंगे। लेकिन चारे की व्यवस्था की चिंता नहीं की गई, पीने के पानी के लिए चिंता नहीं की गई, भोजन के लिए व्यवस्था करने की कोई चिंता नहीं की गई लेकिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए चिंता की गई और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उसको अमली जामा कौन देगा ? ललित किशोर चतुर्वेदी। सारे के सारे राजस्थान में जेहाद छेड़ा जाएगा, आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह राजनीति नहीं तो क्या है? साथ ही ये किस मुंह से कहते हैं कि ऐसे संवेदनशील मानवीय बिन्दुओं को राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए । जिन लोगों ने अयोध्या जैसे मामले को राजनीतिक रंग दिया हो, जिन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी को राजनैतिक रंग दिया हो, जिन्होंने इससे राजनैतिक लाभ उठाया हो, जिन्होंने राजनैतिक लाभ के लिए धर्म का आश्रय लिया हो, जिन्होंने इस देश के अंदर साधू और सन्यासियों को अपने राजनैतिक लाभ के लिए आन्दोलन में झोंक दिया हो वही लोग अब हम लोगों को सीख देना चाहते हैं ।...**(व्यवधान)** सत्य बड़ा कड़वा होता है और सत्य को सुनने के लिए चरित्र का बल चाहिए ।...**(व्यवधान)**... सत्य बड़ा कड़वा होता है और सत्य को सुनने के लिए चरित्र का बल चाहिए । ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)**: साक्षी जी, आप कृपया विषय पर बोलिए ।

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : मैं वही बोल रहा हूं । सत्य बड़ा कड़वा होता है । यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उधर से आया हूं । मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा

हूं । उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने इन पुराने दोस्तों के बारे में क्या कहूं । मेरे नहीं हिन्दुस्तान की जनता के किस्मत के फूल हैं ये लोग, लेकिन जब भी देते हैं जख्म देकर देते हैं, किस कदर वा-अशूल हैं ये लोग । चाहे वह नत्थू राम गोडसे की बात हो, अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो । राजस्थान के क्या हालात हैं, गुजरात के क्या हालात हैं, आज से पांच महीने पहले मुख्य मंत्री ने भयावह स्थिति स्पष्ट कर दी थी तो आपने केवल 102 करोड़ रुपया मंजूर किया । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । महोदय, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने आप पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की दुर्व्यवस्था केंद्र के कारण है । इस देश को आजाद हुए 53-54 साल हो गए लेकिन आप जनता को पानी तक मुहैय्या नहीं करा पाए ।

हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके । हम पीने का पानी इस देश की जनता को उपलब्ध नहीं करा सके, क्या यह शर्म की बात नहीं है ? **(व्यवधान)**

**प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा** (उत्तर प्रदेश) : उन्होंने स्पष्ट किया है कि केन्द्र पर हमने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया । इन्होंने मंत्री जी का दूसरा वक्तव्य नहीं पढ़ा है।...**(व्यवधान)**

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । ...**(व्यवधान)**

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)**: कृपया विषय पर बोलें, मेरा आपसे अनुरोध है।...**(व्यवधान)**

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : मैं नायडु साहब से चाहूंगा कि बैठें । ..**(व्यवधान)**

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)**: आपका समय हो रहा है । विषय पर बोल कर समाप्त करिये ।.

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : मैं उसी पर बोल रहा हूं ।..**(व्यवधान)**

**श्री के. रहमान खान** (कर्नाटक) : इनका मेडेन स्पीच है ।

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : मैं अपने 10 वर्ष के लोक सभा और राज्य सभा के कार्यकाल में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जब वहां भा.ज.पा. में था तो कभी खड़ा नहीं होने दिया । इनका बस चलता तो सदन में नहीं आने देते तो बोलने कैसे देंगे ? मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है । आप बैठे हैं तो बोल पाऊंगा वरना यह नहीं बोलने देंगे।...**(व्यवधान)** मैं गुजरात और राजस्थान की बात कर रहा हूं । यह जो भीषण त्रिकाल संकट है पानी का संकट है, चारे का संकट है और अन्न का संकट है । तीन प्रकार का

संकट सारे के सारे देश में तो है ही लेकिन गुजरात में और राजस्थान में इसने भंयकर रूप ले रखा है । इस प्रकार का संकट कोई इस बार नहीं आया इस वर्ष नहीं आया है । 53-54 वर्ष पहले हम आज़ाद हो गये । प्रति वर्ष अखबारों में सारी की सारी बातें होती हैं। ऐसे ही चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद सारे का सारा मामला कूड़ेदान में चला जाता है । यह तो वही स्थिति हो गई प्यास लगी तो कुआं खोद लिया और उसके बाद मामला समाप्त, मामला रफादफा हो गया । गुजरात और राजस्थान की स्थिति सामने है तो हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली, इकट्ठे हो गये । लेकिन दो बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है । यह बिंदु हैं जो लोग प्यासे हैं, पानी के कारण दम तोड़ रहे हैं, जो भूख के कारण दम तोड़ रहे हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है, तत्काल उनके पास पानी कैसे पहुंचे, तत्काल उनके पास चारा कैसे पहुंचे, तत्काल खाद्यान्न कैसे पहुंचे । अगर कोई अस्वस्थ हो जाता है तो उनके पास दवाएं कैसे पहुंचें । उनकी चिंता करने की आवश्यकता है । दूसरी बात जो चिंता करने की है वह यह है कि 53-54 वर्ष से हम इसका कोई स्थाई हल नहीं निकाल पाए । कैसे इसका स्थाई हल निकलेगा, इस समस्या का हल निकलेगा? पता नहीं हमारा कितना पानी गंगा और अन्य नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है । मान्यवर, मैंने दल वर्ष पहले मथुरा का प्रतिनिधित्व किया, फिर दो बार फरुखाबाद का किया । मैंने स्वयं प्रयत्न करके लाखों रुपये खर्च करके मथुरा में जल निकालने का प्रयत्न किया, बोरिंग किया लेकिन जल स्तर इतना नीचे चला गया यमुना के किनारे पर। पांच वर्ष में एक बार भी आचमन करने की हिम्मत किसी की नहीं बन पाई । 1978 में जो सरकार यहां पर थी, उस सरकार ने यह वायदा किया था कि आने वाले 10 वर्ष में हम हिन्दुस्तान की पूरी जनता को पीने लायक पानी देने का वचन देते हैं । आज 22 वर्ष हो गये लेकिन हिन्दुस्तान की जनता गंदा पानी पीने के लिए विवश हो गई है । न गुजरात में पीने का पानी उपलब्ध है और न राजस्थान में पीने का पानी उपलब्ध है । इस विषय पर निश्चित रूप से सरकार को संवेदनशील होना चाहियें । पर मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील नहीं है । मुझे लगता है कि सरकार के अन्दर हृदयशून्यता है । हम लोग यहां पर जो कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यह अरण्य रोदन जैसा है । इसलिए मीटिंग तो चल रही है पर मीटिंग के परिणाम क्या होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक विद्वान ने कहा है - उछले कूदे टहले, चल फिर के वहीं रहे, जहां थे पहले । हम 54 साल से यहीं रह रहे हैं । उछले, कूदे टहले और चल फिर के रहे वहीं, जहां थे पहले । हालत तो वही है नायडु जी, उससे भी बुरी है । अब जिसके मन में जो आए सो कह ले । आप बार बार कहते हैं कि आपकी सरकार थी । आपकी सरकार थी । यह तो बहुत बुरे थे आप अच्छे आ गये तो आप कुछ कर के दिखा दीजिये न । यह तो बुरे थे तो इनको बदला था।

इन्होंने गलती कर दी तो आप भी गलती करते रहेंगे क्या ? आप बच नहीं सकते जिम्मेदारी से । आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी )** : अब आप समाप्त करिये ।

**डा. स्वामी साक्षी जी महाराज** : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद कर के अपने शब्दों को विराम देता हूं । ...**(व्यवधान)**

**श्री राजीव शुक्ल** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इतने गम्भीर मुद्दे पर बहस हो रही है । यह भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद का विषय बन जाए, यह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीच-बीच में सपा भी आ रही है । वे 10 साल में पहली बार बोल रहे हैं, साक्षी जी को छोड़ सकते हैं लेकिन जो जिम्मेदार सदन के सदस्य हैं जो बहुत पहले से यहां रहे हैं वे भी इसको कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं ? इस पर आप थोड़ी सी सख्ती करें ताकि बिलकुल गम्भीरता से इस पर बहस चलती रहे ।

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to support the appeal made by the hon. Prime Minister for making contributions to the National Calamity Relief Fund. Sir, it is really a national calamity because of the situation that we are facing today. But, we cannot look at the present situation in isolation from what happened last year in Orissa. Sir, the States of Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa need urgent help. Sir, 688 Mandals in Andhra Pradesh, that is almost 65 per cent of the Mandals, are declared as drought-hit areas by the State Government. Some parts of Rayalaseema and Telengana are facing this drought for the third consecutive year. The water level has gone down. Most of the wells and tanks are dried up. There is no water even at the level of 400 ft. in bore wells. Several lakhs of people are leaving villages for towns and other places in search of work and food. Cattle is being sold away to slaughterhouses at throwaway prices. In some districts vast sections of peasants are victims of crop failure also. Agricultural expenses are increasing due to hike in the prices of seeds, fertilisers and pesticides. Debt burden is very heavy because many peasants have switched over to commercial crops which need more investments. In this background, banks, cooperative societies and private moneylenders are pestering the peasants to pay back their dues. Cooperative banks took away their tractors and land and auctioned them. Several peasants who could not bear this insult and injury to their self-respect committed suicide. Mahabubnagar district alone witnessed 16 suicides in a period of one month. Sir, I would like to quote a painful

**7.00 P.M.**

news item from a reputed daily of Delhi, The Hindustan Times. It says, "Already 16 farmers (official figures) committed suicide in this perennially drought-prone district. Their wives are made to work in the houses of moneylenders and landlords to clear the debt, if not, for sexual gratification' says a senior district official". So, Sir, this is the situation. A CPI delegation led by State Secretary Shri Sudhakar Reddy along with some journalists visited these villages on 15th April. These families should be given some ex-gratia relief. Rural indebtedness should be abolished through an Act. Urgent relief should be given to drought-hit areas. Drinking water problem has become very acute in many parts of the drought-affected districts, including some of the coastal districts. The Central Government should come forward to the rescue of this drought-affected State of Andhra Pradesh along with other States like Gujarat, Rajasthan and Orissa. Of course, there is a difference of gravity in the situation. But, yet Andhra Pradesh, as has been demanded by the State Government, needs at least Rs.250 crores as immediate help. In this context, I would like to remind the Central Government that it was Andhra Pradesh which initiated and rushed massive aid to Orissa when it was hit by an unprecedented super-cyclone last year. I hope the Prime Minister would give positive consideration to the plight of Andhra Pradesh. Thank you.

SHRI R.P. GOENKA (Rajasthan): Sir, I thank you for this opportunity to speak. Sir, I had decided to concentrate my speech on Rajasthan. But, somehow, Mr. Ramdas Agarwal's strong speech has incited me to react a little bit.

Sir, he is blaming the Chief Minister of Rajasthan that he did not take up the cause of drought or famine when he, in the middle of November, was in Delhi.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, the hon. Member is not here to defend himself ....*(Interruptions)*....

SHRI RAJU PARMAR: So what? ...*(Interruptions)*... It is his maiden speech .....*(Interruptions)*....

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): It is his problem. It is not the problem of Mr. goenka...*(Interruptions)*...वह भाषण देकर चले गए तो उनकी प्राब्लम है। ...(व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: It is his problem ..*(Interruptions)*... वह नहीं है तो क्या इनकी गलती है? ...(**व्यवधान**)

SHRI R.P.GOENKA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I still remember what Ramdasji has mentioned about the Chief Minister. Whatever he has said is reflected in the record. He also said that his Government did not do anything for four to five months and when they sent its team, the team recommended for an assistance of about Rs. 1,300 crores and they got only Rs. 103 crores or less than 10 per cent of what the State needed. I agree with some of the previous speakers who pointed out whether those Rs. 103 crores have been disbursed. We do not know. In this situation, how one is entitled to talk about like this, I do not know. I would like to submit before you some facts which you very kindly and briefly outlined in your speech earlier. Sir, out of 32 districts in Rajasthan, we have drought in 26 districts; 23,000 villages are affected; 2.5 crores of population is affected due to drought; and 3.5 crores of cattle are affected. The total relief estimated is Rs. 1,300 crores. The Centre has promised to release Rs. 103 crores. They could have promised a little more than what they have promised. What I would like to suggest or what our Chief Minister had said is, "If you cannot proivide funds, give us foodgrains." one of the earlier speakers, I do not remember his name, who was speaking in the distribute foodgrains to the affected areas. it was estimated that 12 crore-manhour relief work is required. I accept that it is not possible for the Centre to accept the demand of the Governments of rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. It is not possible. so, give us food; we will work. Sir, can you imagine the reality in Rajasthan in the last week end? Sir, a hundred tankers are making trips to different villages where there is not water. A hundred tankers are carrying water. On an average, one tanker looks after five villages. We have 23,000 villages. Out of them, half of the villages are facing water scarcity.

Sir, you are a very generous person. But, on time factor-I was watching-you are very strict. So, I would like to end my speech by saying only one thing that either it is funds, or it is food, for heaven's sake, please give us in time. Time is the essence. Do not sit on files. I am not criticising anybody - neither officers, nor the Minister. But whatever you wish to do, please do it in time.

**श्री गांधी आज़ाद** (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद महोदय । महोदय, मैं राजस्थान, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा देश के अन्य क्षेत्र जहां कि सूखे का गंभीर संकट है, इस संकट

की घड़ी में मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से वहां के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं । महोदय, सरकार की व्यवस्था आपदा के अनुसार जितनी तेज होनी चाहिए, वैसी न होकर कुछ लचर है । साथ-ही-साथ वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की भी व्यवस्था खराब होने के कारण वहां हर हाथ को काम मुहैया नहीं हो पा रहा है और जिन को काम मुहैया हो भी रहा है, उन को काम के एवज में प्रशासनिक कारणों से मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है । साथ-ही-साथ पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है जिस के लिए शासन से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं जिस के कारण रोटी, पानी, चारा - सब की तबाही हो रही है । महोदय, मैं इस प्राकृतिक आपदा में इस सदन के माध्यम से अपने सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हम को राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर वहां के प्रभावित लोगों के प्रति सहयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा का डटकर मुकाबना करना चाहिए । धन्यवाद ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : सभी राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है, परंतु सभापति महोदय का निर्देश था कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इस विषय पर चर्चा के लिए कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाए । लेकिन मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना वक्तव्य संक्षिप्त में दें। श्री अनन्तराय देवशंकर दवे ।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा । माननीय वेंकैया नायडु जी ने जो बात कही, मैं उस का समर्थन करता हूं । मैं इस पार्टी, उस पार्टी या किस ने क्या किया, यह कहकर किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन देश में और particulary in Gujarat and Kutch. सर, मैं कच्छ से हूं और वहां की परिस्थिति इतनी भयंकर है कि जिस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । उपसभाध्यक्ष जी, बहुत से मित्रों ने बहुत सी बातें कही । मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता । मैं ड्राउट प्रोन एरिया, जहां बारिस कम होती है, उस संबंध में एक सवाल करना चाहता हूं । मेरा एरिया, डेजर्ट डवलपमेंट एरिया में आता है और इस संबंध में जो कुछ पॉलिसी बनती है, उसे रिव्यु करने की बहुत जरूरत है । अगर हम यह पॉलिसी रिव्यु नहीं करेंगे तो जैसे हम ने सन् 77 में तय किया था कि 10 साल में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन सन् 86 में हुए इंटरनेशनल कनवेंशन में साइन किया और राजीव गांधी मिशन फार्म करने के बाद भी परिस्थिति वही रही ।

आज गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यह पीने के पानी की कमी क्यों हुई है उस पर जब तक हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा । मेरा यहां से साफ

ऐलिगेशन है कि जो कुछ भी यह परिस्थिति हुई है, उसकी दो-तीन वजहें हैं । एक वजह तो वे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको सही अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने जो यहां पॉलिसी फार्म की, उसमें बहुत गलतियां कीं । मैं यह एक बात यहां इसलिए बताना चाहता हूं कि 1 दिसम्बर, 1999 को लोक सभा में एक सवाल पूछा गया था :-

> Whether the Union Government have identified the drought-prone areas in Gujarat?

जवाब दिया गया :

> As intimated by the Ministry of Rural Development, 52 blocks covering an area of 43,933 square kilometres and 10 districts of Gujarat

सुनिए आप, जो मैं कहता हूं, ड्रॉटप्रोन एरिया में कमी जो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, वह ड्रॉटप्रोन एरिया में गई - अहमदाबाद, अमरेली, भरूच, जहां बहुत पानी है, भावनगर, डांग, जहां बहुत बारिश हो रही है, जूनागढ़, पंचमाल, साबरकांठा, वड़ोदरा एंड वलसार । उसमें कच्छ नहीं है, उसमें जामनगर नहीं है, उसमें सुरेन्द्रनगर नहीं है, राजकोट नहीं है, मेहसाना नहीं है और यह गलती स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, सुन लीजिए, यह स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं है, मैंने तलाश की है और मैं सब आफिसिस में गया हूं इस सवाल को लेकर कि किसने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया था और जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, वे प्रोजेक्ट वहां जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के जो प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रॉटप्रोन एरिया है वहां तो कुछ जा नहीं रहा । कैसे हम पहुंचाएंगे पानी ? यह पॉलिसी की दिक्कत है ।

दूसरी बात, तीन डिस्ट्रिक्ट डी.डी.पी. के तय किए गए तीन जगहों पर पानी पहुंचाने के लिए - गुजरात में राजकोट, मेहसाना और सूरत । ताप्ती के किनारे पर ये शहर हैं जहां पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कच्छ नहीं, जामनगर नहीं, सुरेन्द्रनगर नहीं । उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं यह पॉलिसी जब तक सुधरेगी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग़ जब तक ठिकाने नहीं आएगा तब तक यह परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। आज परिस्थिति यह हुई है कि सारे समाज में, सोसाइटी में अकाल हो गया है, खानदानी का, मानवता का अकाल हो गया है । किसलिए ? पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं - महिलाएं पीने का पानी भरने जाती हैं और आपस में लड़ रही हैं, पड़ोसी-पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं । हर जगह पर इस अकाल ने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है कि लोगों में संग्रह करने का एक मेनिया हो गया है । अनाज संग्रह करना, पानी संग्रह करना, यह मेनिया हो गया है । इसकी सारी ऐनेलेसिस हम सब लोगों को बैठकर करनी चाहिए, अगर हम यह नहीं करेंगे तो इस परिस्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है ।

मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि कच्छ और सौराष्ट्र दरिया के, समुद्र के किनारे पर हैं, वहां आरओ प्लांट लगाइए । कच्छ में पिछले 50 साल में यह 32वां अकाल है और सौराष्ट्र व बनातकाठा में 32वां अकाल है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया लगाया, केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है और उनकी ऐन्युअल रिपोर्ट में सैक्रेटरी ने बताया कि '95 percent of the villages of this country are provided with drinking water.'

मंत्री जी, मैं तो यहां से यह ऐलान करना चाहता हूं कि आप इंक्वायरी स्टार्ट करिए कि सेक्रेटरी इस तरह से कैसे गुमराह कर रहे हैं । वहां हमारे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं । हमारे पास पीने का पानी नहीं है । कच्छ में पानी नहीं है । भूतल में पानी नहीं है । आप पानी लाओगे कहां से ? आप रिलीफ वर्क पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं । आपने कहा था कि हर स्कूल में पानी मिलेगा । मैं कहता हूं कि गुजरात में मैंने जिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम कहा, उनमें किसी स्कूल में पानी नहीं है । मैं किसी के ऊपर इलज़ाम नहीं लगाना चाहता । मैं कहता हूं कि यह सिस्टम डिफेक्टिव है । यह सिस्टम फेल्योर है। इसी वजह से यह सब हो रहा है ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि आप कहीं भी जाएं, हर डिपार्टमेंट में ओवर-गवर्नेंस है । कहीं वॉटर रिसोर्सेज़ आ गया, कहीं ऐनावॉयरमेंट आ गया बीच में । कोई नाला बनाना है, डैम बनाना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में आ गया । जब आप एक साथ बैठकर ऐनालिसिस करके इनको निकालेंगे, तभी हम इसका समाधान ढूंढ सकेंगे । दूसरी बात है वॉटर मैनेजमेंट । जब तक हम वॉटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम पानी नहीं पहुंचा सकेंगे ।

अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं । हमारे अहमद भाई यहां नहीं हैं । नर्मदा की बात उन्होंने बहुत दोहराई । मेरा कहना यह है कि नर्मदा का केस कोर्ट में चल रहा है । कोर्ट में जो केस है, वह रिहैबिलिटेशन का है, हाईट का केस नहीं है । हाईट का केस तो तय हो गया है ट्राईब्यूनल में । अब जो रिहैबिलिटेशन का केस है, वह भी तय हो जाना चाहिए । आप मध्य प्रदेश की सरकार को समझाइए कि वह आदिवासियों के रिहैबिलिटेशन के लिए जमीन दे दे । तब गुजरात में नर्मदा का पानी बहेगा और सारे सौराष्ट्र, सारे नॉर्थ गुजरात और सारे कच्छ में पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी । वही एक रास्ता है । तो वॉटर मैनेजमेंट, नर्मदा और समुंदर का पानी मीठा बनाने की जो योजना है, उसे आप कार्यान्वित कीजिए । हम आपको उसमें पूरा सहयोग देंगे । मैं गवर्नमेंट पर कोई इलज़ाम नहीं लगा रहा हूं । गुजरात की गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर

रही है लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं । उनके पास पैसे कम हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात सरकार को और पैसा दे । धन्यवाद ।

***श्री के.एम. खान** : बहुत-बहुत शुक्रिया नायब सदर साहब । मैं आंध्र प्रदेश से इस ऐवान में नुमाइंदगी करने के लिए भेजा गया हूं और सूखे की सूरते-हाल, खुश्कसली की सूरते-हाल आंध्र प्रदेश में किसी तरह से गुजरात और राजस्थान से कम नहीं है । इससे पहले मेरे पेशरो साथियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में आज लोग सूखे की वजह से, क़हतसाली की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं । स्टारवेशन डेथ वहां पर हो रही हैं और लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । जानवर चारा न होने की वजह से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मर रहे हैं । ऐसी सूरते-हाल वहां पैदा हुई है ।

महोदय, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के तकरीबन 18 अज़ला खुश्कसाली के शिकार हैं और 18 अज़ला में कुल 668 ऐसे मंडल हैं जहां ये सूरते-हाल बहुत संगीन है और अगर इस पर फौरी तवज्जह नहीं दी गई तो हमें इस बात का डर है कि और बहुत से लोग फाकाकशी से मरेंगे । अभी कुछ साथियों ने कहा कि किसानों ने जिन बैंकों से कर्ज़ा लिया, जिन प्राइवेट साहूकारों से कर्ज़ा लिया, वे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वे उनका पैसा वापस करें । एक तरफ तो रियासत की सरकार यह कहती है कि हम कर्ज़ों को पोस्टपोन करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनसे कर्ज़ा वापस लिया जाए । ऐसा रोज सुनने में आ रहा है कि वे किसानों के पास जाकर उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं जिसके कारण खुदकुशी की कई घटनाएं रियासत में देखी गई हैं। रियासती हुकूमत कहते हैं हमारे पास फंड की कमी नहीं है, बहुत फंड है। हम इस पर खर्च कर सकते हैं लेकिन जब किसान जिला कलेक्टर के पास जाता है, मंडल आफिसर के पास जाता है तो उसे जवाब दिया जाता है कि सरकार के पास इस मसले से निबटने के लिए, सूखे से निबटने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है तो ऐसी स्थिति आंध्र प्रदेश की है इसमें दो राय नहीं है। सरकार अपनी पौलिसीज की वजह से इस लेविल पर पहुंच गई है जिसको आप दिवालियापन कह सकते है, सरकार इकानॉमिकली बैंक्रप्ट हो चुकी है और उसके पास पैसे की शक्ति नहीं है जिससे वह इस सूरते हाल का मुकाबला कर सके।

**श्री रूमन्दला रामचन्द्रैया** (आन्ध्र प्रदेश) : शक्ति बहुत ज्यादा है।

---

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

***श्री के.एम. खान** : आपकी बारी आए तो बोलिए, मुझे बोलने दीजिए।

राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपए की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी। यह बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे संगीन मामले में मरकज़ की हुकूमत ने सिर्फ 75 करोड़ रुपए देकर चुप्पी साध ली हैं और जो एक रत्ती के बराबर राशि है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि तो यह सूरते हाल आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना का सारा इलाका इससे मुतासिर है।

मैं एक और मामले में आपकी तवोज्जह दिलाते हुए अपनी बात खत्म करुंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं और मेरा तेलंगाना से ताल्लुक है। मेरे एक और दोस्त महबूब नगर के यहां बैठे हैं। वह भी इस बात से वाकिफ हैं कि इस जिले में सूरते हाल और जगह से बहुत ज्यादा संगीन हैं। महबूब नगर में हर साल जो बारिश होती है वह 7.54 (एम.एम) मिलियन मीटर बारिश होती है लेकिन इस साल इस जिले में सिर्फ 3.66 (एम.एम) मिलियन मीटर बारिश हुई जिसकी वजह से इस जिले के 64 मंडल जो हैं वह इसके ज्यादा शिकार हैं। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आपके साहूकारों का दबाव बढ़ा, आपके कोआपरेटिव बैंक का दबाव बढ़ा, आपके नेशनलाइज्ड बैंकों का दबाव बढ़ा तो महबूब नगर जिले के अंदर के मैं दो-चार वाकयात आपको बताऊं कि कहां-कहां कितनी खुदकुशियां हुई हैं। गंगापुर विलेज है, हैदराबाद से 60 किलोमीटर पर जड़चल्ला है। वहां दो किसानों ने खुदकुशी की। इसी तरह से गोकुली विलेज में दो किसान मरे, उन्होंने आत्म हत्या करली। बारा नगर, अप्पाजी पल्ली विलेज जो सिमाजी मंडल में है वहां किसानों ने आत्म हत्या की। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब यह खबरें आ रही हैं कि जो कॉटन फार्मर्स हैं, जो कॉटन ग्रोवर्स हैं उन्होंने भी काफी तादाद में आत्म हत्या की है। **(समय की घंटी)** इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस नाजुक स्थिति के कारण वहां के जो मजदूर हैं उनका माइग्रेशन हो रहा है। वे अपने गांव छोड़कर नौकरी की तलाश के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं के इसकी वजह से वहां और क्या सूरते हाल पैदा हो रही है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है जो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं वे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं और खुदकुशी की आम बात हो रही है इसलिए मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं केन्द्र की सरकार से मुतालिवा करना चाहता हूं कि वह इस मामले पर संजीदगी से गौर करें।

सदर साहब, खुद हमारे शहर हैदराबाद के अंदर जो पीने के पानी की समस्या है वह बहुत नाजुक समस्या है। दो दिन में एक बार पानी आता है एक घंटे, दो घंटे के

---

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

लिए और वह भी रेग्यूलर नहीं आता है। हैदराबाद शहर की जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है इस पर सरकार को तवोज्ज़ह देने की जरूरत है। **(समय की घंटी)** मैं अपनी बात खत्म करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह सारा मामला स्टेट गवर्नमेंट के बस का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने सरकार से रिलीफ की जो मांग की है उस पर फौरी गौर की जरूरत है। अगर इसमें देरी होगी तो इस बात का अंदेशा है कि हालात संगीन होंगे और लोग भुखमरी का शिकार होंगे, मौत का शिकार होंगे, खुदकुशियों की तादाद बढ़ेगी और इससे हमारी बहनें, हमारी मांएं सब परेशानी का शिकार होंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से और इस सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि फौरी तौर पर जो रिलीफ का काम है उसको बढ़ाया जाए, रिलीफ के सेंटर कायम किए जाएं और खास तौर से उन लोगों के लिए जो नौजवानों के माइग्रेशन की वजह से भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं उनके लिए रिलीफ के सेंटर खोलें ताकि उनको इस मुसीबत से निज़ात दिलाई जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the nation is reeling under severe drought. This is one of the worst drought conditions it had ever experienced. The States of Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, some parts of Orissa, Maharashtra, Madhya Pradesh and some parts of Karnataka which are adjacent to Andhra Pradesh are all facing severe drought conditions.

In Andhra Pradesh, the south-west monsoon has failed this year. The rainfall during June to September, 1999 had been uneven, with long dry spell during the critical stages of planned growth. Then, 512 mandals out of 1,099 rural mandals received scanty and insufficient rainfall. The entire crops that were raised have withered away. Our Chief Minister has taken special care to visit the worst-affected areas and steps have been taken for rescheduling of loans, sanctioning of special crop loans, etc., in the drought-affected mandals. In the month of October, 1999, the total loss was estimated at Rs.2566.91 crores. Our Chief Minister wrote letters to the Central Relief Commissioner and to the hon. Prime Minister for sanctioning Rs.720.36 crores as the Central assistance, Relief Fund to combat the drought situation. But so far only Rs.75 crores have been released.

Due to severe summer prevailing in Andhra Pradesh, covering about 688 mandals, that is, more than half of the area of the State is reeling under severe drought. Telangana and Rayalaseema areas are the worst-affected. Whatever little crops, the farmers have raised, have withered away; and the

water resources dried up. The situation is very grave and near famine conditions are prevailing in these areas. Lands have become parched. There is no fodder for the cattle. Farmers are in distress. They are disposing of their cattle. Many of the cattle are dying due to hunger.

As far as the drinking water is concerned, wells have dried up. The ground water table has receded in some areas. People have to spend almost a day in travelling and standing in the queues for getting little water from nearby places where the wells are having some water. The situation is getting aggravated day by day; and in many places riots have broken out. Since the situation is assuming a life and death dimension, it is feared that ..*(Time-bell)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude.

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Two minutes more, Sir. The States like Gujarat and Rajasthan have made appeals to the non-governmental organisations, private sector, etc., to support the endeavour of the States to tackle the drought crisis. I am happy that the Prime Minister has appealed to the people to contribute liberally to tide over the crisis. Our Chief Minister is seeking the help of all, to face the crisis. In this connection, it may be recalled, the immediate assistance and relief measures offered by Shri Chandra Babu Naidu to the people of Orissa, when they were severely hit by cyclone last year, was appreciated by all the people in the country. But, now, Andhra Pradesh itself has become a victim of natural calamity, reeling under the grip of severe drought and yearning for assistance from all Corners. Therefore, I appeal to the Central Government to release immediately Rs.500 crores to tide over the crisis. Thank you.

**श्री संतोष बागड़ोदिया** : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं टू दा पाइंट जल्दी से जल्दी बोलने की चेष्टा करूंगा। राज्य के 26 जिलों के 23406 गांवों को दिनांक 9 जनवरी, 2000 को अभावग्रस्त घोषित किया गया। इससे 261 लाख जन संख्या एवं 345 लाख पशु धन प्रभावित हुआ है। अकाल की इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर राहत गतिविधियां चलाये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत गतिविधियां संचालित करने के लिये जो योजना बनाई गई है उसके लिए अनुमानतः 1311 करोड़ रुपये (1034 करोड़ रुपये मजदूरी पर, 112.20 करोड़ रुपये पशु संरक्षण पर और 164.70 करोड़ रुपये पेयजल व्यवस्था पर) की आवश्यकता है।

राज्य के आपदा राहत कोष में जुलाई, 2000 तक मात्र 106 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हो पायेंगे। अतः इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये लगभग 11.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता रहेगी जिसके लिए केन्द्र सरकार को नवम्बर, 1999 में ज्ञापन दिया गया। भारत सरकार ने सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल जनवरी में भेजा।

केन्द्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपद राहत समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च 2000 को हुई, उसमें राज्य को 102 करोड़ की सहायता के संबंध में निर्णय लिया गया। महोदय, यह अंडरलाइन करने की बात है कि वह राशि अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त होनी शेष है । वह 102 करोड़ रुपय भी अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं । नायडु साहब, आप कुछ करिए । 28.3.2000 को प्रधान मंत्री महोदय को पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता तुरन्त देने के लिए मुख्य मंत्री ने कहा । 2.12.1999 को मानमीय प्रधान मंत्री महोदय को पत्र लिखकर निवेदन किया गया कि राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु "काम के बदले अनाज योजना" चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनाज आबंटित किया जाए । इस वर्ष ऐसे राहत कार्यों को हाथ में लिया गया है जिनसे कि अकाल के प्रभाव को रोका जा सके । अभावग्रस्त जिलों में 15,824 राहत कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 9,455 राहत कार्य चल रहे हैं । फरवरी और मार्च 2000 के लिए श्रमिक सीमा - यह थोड़ी सी रिपोर्ट आप देख लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि गोयंका साहब ने बताया नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में बता दूं । मैं सिर्फ एक मिनट में खत्म कर दूंगा । 69,899 श्रमिक काम कर रहे हैं । इस प्रकार 3 लाख 52 हजार 495 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है । 1 अप्रैल से राहत कार्यों पर श्रमिकों की मजदूरी दर 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन कर दी गयी है । मेरा अनुरोध केवल इतना ही है । अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि इतने राज्यों में अगर सबको हजार-हजार, पांच सौ, सात सौ करोड़ दिये जाएं तो दिल्ली की सरकार कैसे दे सकेगी ? मैंने हिसाब लगाया कि कुल मिलाकर चार-पांच हजार करोड़ रुपये का हिसाब बैठता है । दो लाख करोड़ रुपये का हमारा बजट है । उसमें चार-पांच हजार करोड़ रुपये देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । इसलिए नायडु जी, आप आंध्र प्रदेश को दिलाइए, सभी स्टेट्स को दिलाइए और समय पर दिलाइए । अगर अभी तुरन्त आप राहत नहीं देते तो बाद में देने से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आश्वासन नहीं चाहिए, ऐक्चुअली यह पैसा उन्हें मिले जिससे उनके काम में आए । धन्यवाद ।

**श्री ललितभाई मेहता** : उपसभाध्यक्ष जी, देश के विभिन्न भागों में कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं - कभी भूचाल आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी चक्रवात आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हम इन चारों प्राकृतिक विपदाओं का अनुभव करते हैं । पिछले साल चक्रवात आया था, इस साल सूखा पड़ गया है । थोड़े साल पहले वहां पर बाढ़ भी आ गयी थी । गुजरात की जो भू रचना है, वह ऐसी है कि जिसके कारण हमें पीने के पानी के लिए बरसात के पानी पर निर्भर करना पड़ता है । 66 प्रतिशत जो जमीन का विस्तार है वह पत्थर वाला है और 34 प्रतिशत जो बाकी विस्तार बचता है, उसमें से चार प्रतिशत विस्तार ऐसा है जो दरिया के किनारे लगा हुआ है इसलिए वहां पर खारा पानी आता है । जमीन के पानी का सवाल ही गुजरात में नहीं है, वहां बाहर से ही पानी लाना पड़ता है । सरफेस वॉटर है तो उसका ही उपयोग करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है । इसलिए 1981 से 1990 तक के दशक में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वॉटर ऐंड सैनीटेशन डीकेड मनाने का निर्णय किया था, उस वक्त गुजरात में यह योजना बनी थी और पीने के पानी की योजना बनने के बावजूद भी गुजरात पानी के बिना तरस रहा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि गुजरात का ऐसा विस्तार है - देश का कुछ विस्तार ऐसा है जहां पर सूखे का असर रहता है । देश के 19 प्रतिशत जिलें ऐसे हैं, 16 प्रतिशत देश का भौगोलिक विकास ऐसा है और 11 प्रतिशत आबादी ऐसी है जहां पर अकाल रहता है लेकिन गुजरात के 60 प्रतिशत जिले ऐसे हैं और 43 प्रतिशत भौगोलिक विस्तार ऐसा है तथा 27 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो अकालग्रस्त है । यह परिस्थिति हमारे सामने है । आज जो परिस्थिति है, उसके कारण गुजरात में खेत का जो उत्पादन आएगा, वह सिर्फ सात प्रतिशत जमीन से, जहां पर बीज बोया गया था, उसमें से आएगा ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : आप केवल सुझाव दीजिए और संक्षेप में बोलिए ।

**श्री ललितभाई मेहता** : मैं सुझाव रखना चाहूंगा कि अगले वर्ष - यानी खरीफ सीज़न इस बार नहीं होगा, अगले खरीफ सीज़न के लिए खाद, बीज और खेती के लिए इनपुट्स की व्यवस्था करनी होगी । सारे देश में जो पानी के विस्तार हैं, वहां से पानी देश के विभिन्न भागों में ले जाया जा सकता है, ऐसी योजना भूतकाल में बनाई गई थी । तो क्या हम यह नहीं कर सकते कि देश के सारे ज़िलों को पाईपलाईनों से जोड़ दें ? महोदय, सौराष्ट्र से, सलाया से मथुरा तक तेल की एक पाईपलाईन लगी हुई है तो क्या पानी के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ?

महोदय, जो बहुत कम बारिश वाले विस्तार क्षेत्र हैं, वहां के लिए जो संशोधन हुआ है, उसके तहत यह तय किया गया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8000 लीटर पानी बारिश का

वहां पड़ता है लेकिन उस पानी को हम संग्रह नहीं कर पाते हैं, अगर इस पानी को हम संग्रह करें तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को 300 लीटर पानी जो पीने के लिए और सिंचाई के लिए चाहिए, वह हम उसे दे सकते हैं । लेकिन पिछले कई सालों में इस पानी को प्रिज़र्व करने के लिए और कंज़र्व करने के लिए योजनाएं नहीं बनीं । गुजरात सरकार ने इस बार 10,000 चेक डैम बनाने की योजना बनाई जिसके लिए उसने सौ करोड़ रुपए तय कर दिए । अभी पिछले दो महीने में 2000 से ज्यादा चेक डैम बन गए हैं जबकि पिछले 53 सालों में सिर्फ 1900 चेक डैम बने थे । तो इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

SHRI AIMADUDDIN AHMAD KHAN (DURRU) (Rajasthan): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the drought situation in my State of Rajasthan. There were certain aspersions cast on the State Government by some of my colleagues from the other side, and a lot of clarifications were given from this side. The State Government was in touch with the Government of India from the very beginning, and the matter was brought to the notice of the Government of India in October. The matter was brought to the notice of the Government even through the forum of this hon. House on the 2nd March, through a question put specifically about the drought situation in Rajasthan. It is a matter of great regret that in spite of so many representations made to the Government of India, the meeting of the NCRF was held on 27th of March, that is, six months after the first representation of the State Government of Rajasthan was received by the Government of India. Nonetheless, I wish now to bring to your notice some of the points that were missed out by my colleagues here. The rainfall in 1999 in Rajasthan was 450 mm, as against the normal rainfall of 533 mm, the loss of production in 1999 of bajra was 60 per cent which was targeted at 21.25 lakh tonnes; the loss of production of maize was 48 per cent with the target of 10.6 lakh tonnes and the loss of production in respect of pulses was 72 per cent with the target of 5.3 lakh tonnes. These are some of the points I wish to bring to your kind notice to show the kind of situation that is being faced by the State Government. The State Government has, at present, engaged four lakh labourers working on relief works at the rate of Rs. 60/- per person per day, which is the minimum wage. The monthly expenditure is over Rs. 60 crores. If we add to this Rs. 20 crores for material, the approximate monthly requirement is over Rs. 80 crores. In the coming months of May and June, this number of the workforce will increase. There will be corresponding

increase in the requirement of funds. Similar heavy amounts are being spent on cattle camps and drinking water. If we add all the expenses, the State is spending Rs. 3 crores per day on the management of drought relief. The drinking water expenses on tankers will go up from Rs. one crore to Rs. four crores per day. Already, the temperature is four to five degrees above the normal.

And this will worsen in the next two months. The grain supplied under the PDS has been increased from 10 kilos to 20 kilos per person per day. Though it can be obtained at concessional rates, yet it has to be paid for. The Government of India is giving a total aid of Rs. 100 crores for a period of one month. There has been a lot of talk from both sides of the House about the various long term measures which have to be taken. You yourself had mentioned about water management and water harvesting. Just for the sake of my colleagues, I would like to illustrate my point by citing an experiment that has been conducted by an NGO in the district of Alwar in Rajasthan. It is called **Taran Bharat Sangh.** You might remember that last month, the hon. President of India had gone there to honour this NGO for the water management programme which they are conducting. When they started the work of water management there, there were some streams and rivers which had been dry for the last 50 years. But after doing small projects on water management, I am glad to say that the river has started running again and there is plenty of water and there is water in the tubewells also. So, this is a programme which can be and should be taken up on a war-footing so that this recurring problem of drought, which is prevalent in Gujarat and States like Rajasthan, can be dealt with.

Also, here, I would like to make one last point about another long-term plan that we should take up in the field of agriculture. Up till now, we have been relying too much on chemical fertilisers and pesticides. We have forgotten our age-old, traditional, farming, that is, organic farming. It was mentioned in our Shastras and Puranas thousands of years back. I regret to say that though we have forgotten it, in 1920's a European Agro-Economist, Rudolf Styner, studied the Shastras and the Puranas and started propagating the idea of organic farming in Europe and America. I would like to draw the attention of the Government to this fact. And here we have a Government which is talking about going back to our culture and our ways of life. This is what I wanted to say.

Before I conclude, I would like to just make two-three points to be taken up on a long-term basis so that this annual feature of drought can be faced. In order to immediately face the situation, I would like to request the Government of India to solicit the help of the our defence forces, especially, the Army, to help the various States in these relief operations. Since they are a very well-organised part of our society, I would request the Central Government to take into consideration the appeals of the various State Governments, including the State Government of Rajasthan, for further help in the matter. Thank you.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): At the outset, the whole nation, particularly, the drought-affected States, are very much grateful for the appeal that has been made by the hon. Prime Minister. At the same time, my State is also thankful and grateful to the Ministry of Agriculture and to the Ministry of Finance for releasing an instalment of Rs. 86 crores in last week. But, Sir, the drought situation which the various States, particularly, Gujarat, are facing now has never been faced by them since the last 101 years. It was 101 years back that there was a drought like this, and it was called the Chapparia drought. It was in 1956 Samwat. But this drought spell has created a worse situation in the State. It was anticipated in the month of August, before the Meteorological Department made an announcement. A meeting at the State Cabinet level was held on 23rd August, 1999. I just want to remind my friend, Mr. Brahmakumar Bhatt, that the second meeting was held on 5th September, 1999 and the third meeting was held on 16th September, 1999. Thereafter, there was a meeting every week. As far as drinking water is concerned, there is scarcity. It is not that the State is not making efforts. They are making efforts. There is a raskavare system, a water supply system, which has been getting water from Mahi project which is 180 kilometres away. I would like to remind my friends who have spoken in favour of Gujarat and other States that there are four districts where there are several projects, but there is not a single drop of water in many projects. Rajkot is having 28 projects. Out of that, in 18 projects there is not a single drop of water. Surendranagar is having 12 projects. Out of that, in 10 projects there is not a single drop of water. In Jamnagar there are 25 projects. Out of that, in 18 projects there is not a single drop of water. In my district there are 15 projects. Out of that, in 13 projects there is not a single drop of water. There are only two rivers, Mahi and Panam, and water is being sent to Baroda and Ahmedabad from Kadana and Vanakbori projects through raskavare system.

Our Government is making every effort to supply water. When scarcity is there, relief work is required. When scarcity is there, food supply is required. When scarcity is there, wages need to be offered to the common people. This has also been done. At present, people are fetching water from three or four kilometres away. We have started providing hand-pumps. We have also started giving immediate relief. Like Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan and Karnataka are also affected. Cattle are starving. We don't have enough fodder. Every day we get one goods-train of fodder. But it is not enough to feed the cattle. Therefore, a plan is required. My friend was saying that when there was scarcity our Chief Minister was sitting in air-conditioned rooms. I would like to say that the preliminary report was sent to the Central Government, seeking assistance to the tune of Rs.930 crores, in the month of October. Subsequently, reports were submitted every week. The State Government has also organised meetings at the tehsil level every Friday and at the district level every Saturday. I request the Government, through you, Sir, to provide monetary assistance which is badly needed. I know that the Centre doesn't have much money with the Calamity Relief Fund. But the resources can be created by seeking assistance from the cooperative sector and the banks. Some nationalised banks may also be asked to assist. Some donations or contributions may also be made to the Chief Minister's Relief Fund and the Prime Minister's Relief Fund and the State can be provided assistance from that.

**श्री राजूभाई ए. परमार:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में सूखे की गंभीर समस्या पर इस हाउस में चर्चा हो रही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, कई सालों से हर साल हम लोग यहां पर ड्राउट सिचुएशन के बारे में या फ्लड सिचुशन पर चर्चा करते हैं । लेकिन जो सुझाव आते हैं, जो डिमांड आती हैं स्टेट्स की तरफ से, एम0पीज की तरफ से कि इसके लिए परमानेंट साल्यूशन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । हमारे आदरणीय अहमद पटेल जी ने, हमारे नायडू जी ने जो सुझाव इस पर दिए हैं इसके बारे में सभी पार्टियों को मिलकर कुछ करना चाहिए और इसके लिए कोई फंड बनाना चाहिए ताकि बार बार जो फंड का अभाव होता है वह न हो । उपसभाध्क्ष महोदय, गुजरात के 25 जिलों में से करीब 17 जिले सूखे से प्रभावित हैं । गुजरात के 230 तालुकाओं में से 153 तालुका इससे प्रभावित हैं और 18727 गांवों में से 9421 गांव इससे प्रभावित हैं । गुजरात में खासकर अमरेली, पातन, पोरबंदर, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर और कच्छ आदि जिले ज्यादा सूखे से प्रभावित नजर आते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा

अभी हमारे ब्रह्मकुमार भट्ट जी ने बताया कि सितम्बर महीने में ही हमको पता चल गया था कि मानूसन फेल हो गया है, बारिश कम आई है। अगर उसी समय स्टेट गवर्नमेंट ने एडवांस प्लानिंग करके इस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना दे दी होती या मेमोरेंडम दे दिया होता, या अपनी डिमांड उसके सामने रखी होती तो आज जो यह स्थिति पैदा हुई है वह स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने दिसम्बर, 99 में स्कियरसिटी डिक्लियर की और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पर बकाया था ....

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: The relief work was started only after 15th of October. That is what the Scarcity Manual of the Central Government speaks of.

**श्री राजूभाई ए. परमार** : दिसम्बर 1999 में स्कियरसिटी डिक्लियर की गई और गुजरात गवर्नमेंट को जो पैसा देना था 992 करोड़ रुपया उसमें करीब 55 करोड़ रुपया ही गुजरात गवर्नमेंट को दिया गया। और यह भी कब दिया गया? मार्च के एंड में । आप बताइएगा कि यह पैसा गुजरात गवर्नमेंट को कब मिला? मार्च एंड में पैसा मिला। आप बता रहे थे कि गुजरात गवर्नमेंट ने अक्टूबर से रिलीफ वर्क स्टार्ट कर दिया।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: It could be started only after 15th of October. That is what the Scarcity Manual of the Central Government speaks of.

**श्री राजूभाई ए. परमार** : उपसभाध्यक्ष जी, कहने का मतलब यह है कि यदि टाइमली ऐक्शन लिया जाता तो आज जो समस्या गुजरात में खड़ी हुई है, खासतौर से पीने के पानी की, पशुओं के लिए घास और चारे की वह पैदा नहीं होती । हम किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आनरेबल प्राइम मिनिस्टर दो दिन के लिए गुजरात के दौरे पर थे।। अगर चीफ मिनिस्टर बीमार थे तो उनके सीनियर मिनिस्टर थे जो उनको एक दो सूखे एरिया में ले जाते जैसे कच्छ है, जामनगर है, राजकोट है । अगर वे ऐसा करते तो कम से कम प्रधानमंत्री को पता चल जाता कि गुजरात में सूखे की स्थिति क्या है। हमारे कहने का मतलब यह है कि उनके दौरे से कुछ और सहूलियतें गुजरात को और मिल सकती थी । लेकिन इसमें हमारी गुजरात गवर्नमेंट फेल रही । दूसरा, जो गुजरात में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने स्कियरसिटी मास्टर प्लान बनाया है और इसमें 6312 गांवों को रखा गया है। 69 शहर और 13 म्युनिस्पल कारपोरेशन उसमें रखे गए हैं लेकिन इसके जरिए बहुत कम गांवों में पीने का पानी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचाया गया है । यह एक

बहुत गंभीर मसला है । मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पानी की वजह से वहां पर लोगों में झगड़े हो रहे हैं, खासतौर पर जो भावनगर की बगल में वरतेज गांव है वहां पर उन्होंने हाई वे पर बंद डिक्लियर किया क्योंकि वहां उनको पानी नहीं मिल रहा था । पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और पुलिस की तरफ से फायरिंग भी हुई । मेरा खुद का जिला सुरेंद्रनगर है, वहां के वीरपुर गांव में महिलाएं कुएं में उतरती हैं, रस्सी से अपने आप को बांध कर नीचे जाती हैं, ऊपर जो महिलाएं होती हैं उसको खींचती हैं और पानी बाहर आता है। फिर दूसरी महिला नीचे जाती है । पांच-पांच, दस दस मील दूर तक महिलाओं को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है । यह स्थिति आज गुजरात में है । इसके बारे में आपके माध्यम से मेरी गुज़ारिश है कि जल्दी से जल्दी कुछ व्यवस्था की जाए और गुजरात गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल अस्सिटेंस मांगी है, उसको जल्दी पहुंचाई जाए ताकि आने वाले दिनों में पानी की समस्या हल कर सके । दूसरी बात यह है कि वहां फॉडर की बहुत कमी है । अहमदाबाद जिले के वीरगांव तालुका के वीरपुर गांव में हमारे गुजरात में लोग गाय की पूजा करते हैं और इसके वध पर प्रतिबंध भी है लेकिन वीरपुर गांव में एक हजार से ज्यादा गाय चारे की कमी के कारण मर गई । जब विधान सभा में इस पर चर्चा हुई और प्रश्न उठाया गया तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम पिंरापोल को पैसा नहीं देते हैं । अब इतना अहम मसला था एक हजार गाय वहां मर गई और पूरे पिंरापोल के ट्रस्टी लोग जब फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने गये, हाऊस में इमरजेंसी में चर्चा हुई तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि ऐसे तो बहुत पिंरापोल वाले पैसे का डिमांड करेंगे तो हम कैसे दे सकते हैं। बाद में जब प्रेशर आया तब जा कर के पैसा देने की बात कही । कहने का मतलब यह है कि जब एक और अपना पशु धन मर रहा है तो थोड़े पैसों की वजह से उनको परेशानी न हो, यह भी हमको देखना चाहिये । जहां तक रिलीफ वर्क की बात है, यह कहा जाता है कि उनको टाइम से पैसा मिलता है । लेकिन ऐसी बात नही है। हर वीक में उनको पेमेंट हो जाना चाहिये रिलीफ वर्क में जो भी मजदूर काम करता है उसको दो-दो, तीन-तीन हफ्ते तक उनको मजदूरी नहीं मिलती है । वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती है । वहां पर शैड भी नहीं है जहां पर मजदूर दोपहर को खाने के टाइम पर आराम से बैठ सकें। यह सब मसले वहां पर हैं । आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदरणीय पटवा जी से मेरी खास गुज़ारिश है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 922 करोड़ रुपये मांगे हैं जिसमें से अभी तक केवल 54 करोड़ ही दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी धनराशि वहां पहुंचाई जाए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, यदि टाइमली हेल्प नहीं मिलेगी, बाद में पैसा मिलेगा तो उसका कोई मतलब



20—160/RS/ND/2000

**8.00 P.M.**

नहीं रहता है । मैं आपके माध्यम से फिर गुज़ारिश करता हूं कि माननीय पटवा जी जल्दी से जल्दी पैसा भेजने की व्यवस्था करें। धन्यवाद ।

**श्री भारतेंदु प्रकाश सिंहल** : माननीय वाइसचेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुझे केवल दो बातें कहनी हैं । एक तो यह कि सूखा ऐसी चीज़ है जो बहुत पहले से दिखाई देने लगता है और उसके लिए पूरा मेनुअल बना रखा है, उसके हिसाब से यदि काम नहीं हुआ है, टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं हुआ है तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन अनिवार्य है । पार्लियामेंट इस बात की डिमांड करे कि क्या एक्शन लिया गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हों या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हों । उनके खिलाफ एक्शन ले कर बताया जाए । दूसरी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट्स से डिमांड आ रही हैं । अफसोस की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की क्रेडिबिलिटी लो हो गई है । जहां तक मेरी जानकारी है जब मैं सरकारी अधिकारी था और काम करता था तो यह कहते हैं कि सौ रुपये चाहियें तो छः सौ मांगो वह एक चौथाई या आधा कर देंगे । यह टोटल खर्च सेंटर से निकालना चाहते हैं । सेंटर को धोखा देते हैं । किस को धोखा दे रहे हैं, हम नहीं समझते लेकिन यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सच्ची फिगर्ज़ प्रस्तुत नहीं करती हैं । क्रेडिबिलिटी गैप है । मेरा निवेदन है कि पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए जो जगह जगह जाए ।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order. I think this kind of a sweeping generalization about the State Governments goes beyond the competence of this House. This is unfair.

SHRI B.P. SINGHAL: This is what is happening.

SHRI NILOTPAL BASU: Whatever may happen. But it is beyond his competence to speak in such sweeping terms about all the State Governments.

SHRI B.P. SINGHAL: I have the competence to speaking because I have worked in....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, you give your ruling then. If he is challenging this....*(Interruptions)*...Then, let Mr. Venkaiah Naidu get up and express his views on this...*(Interruptions)*...This is the Council of States....*(Interruptions)*... Sir, this is not done. We don't expect this kind of a statement that the Central Government is more eminently eligible for doing all thee things, that whatever they are saying is correct, and that whatever the State Governments are saying is wrong....*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: I have seen it happening.....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: He does not understand the implications of what he is saying.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, now, may I continue?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Yes.

SHRI B.P. SINGHAL: There has been a suggestion that a committee of Parliament should go to the drought-affected areas and that it should actually evaluate what the real requirement of each State is so that something could be done. I have been sitting here right from 5 o' clock waiting for Members to suggest what they themselves are going to do for droughts that have become a menace in this country. I am sorry to say, not one suggestion came from any quarter. I, therefore, personally, feel that in order to improve the drought situation, we have the MPLADS from which each of us can donate Rs.30 lakhs to the Prime Minister's Relief Fund, create a Calamity Relief Fund and help the drought-affected States of the country. This is my suggestion. I pray to the Members of the House to kindly be generous enough to give this money to the Prime Minister's Relief Fund. It can, readily, be available to the Prime Minister for immediate disbursement to the States...

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): That won't be a contribution by Members.

SHRI B.P. SINGHAL: Like we paid Rs. 5000 in the case of Orissa, we can pay our one month's salary to the Prime Minister's Relief Fund. This is the second suggestion. These are the two contributions that I would urge upon the Members to make for the Prime Minister's Relief Fund so that the Government can take immediate action. Thank you.

**श्री मूलचन्द मीणा**: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के अंदर एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। इस देश के लिए हम यह कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक आपदाओं का देश है क्योंकि इस देश के अंदर किसी न किसी हिस्से में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से लोग पीड़ित रहते हैं। लोगों के सामने समस्याएं रहती हैं। किसी जगह भीषण अकाल की समस्या रहती है तो कहीं बाढ़ की समस्या रहती है, कहीं प्राकृतिक तूफान की समस्या रहती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं जिससे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। इस प्रकार की समस्याएं इस देश के अंदर आती रहती हैं। 50 साल की आजादी के बाद भी हम इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं जिससे इन प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिल सके। पंडित जवाहर लाल जी के जमाने

में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने का एक प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन यह योजना कार्य रूप में नहीं आ पायी इसी कारण से 50 साल के बाद भी आज जैसी भी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं हम उनसे जूझते रहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि अकाल, सूखे और पेयजल की समस्याओं के ऊपर चर्चा हो और इस हाउस के अंदर पार्टी के स्तर से नहीं उठकर केवल राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहें। यह हमेशा होता रहा है जब जब भी चर्चा हुई है। एक दूसरी सरकार या एक दूसरी पार्टी की सरकार के ऊपर लांछन लगाकर इन चर्चाओं को समाप्त कर दिया जाता है। उस समस्या को दूर करने के लिए जो भी कमियां या खामियां रही हैं या जो भी आर्थिक या पैसे की समस्या के कारण हम उस समस्या को दूर करने में काम नहीं कर पा रहे हैं उसकी ओर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की बात हो, ध्यान नहीं जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए जितना पैसा चाहिए आज देश के अंदर राज्य सरकारें उसके लिए सक्षम नहीं हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के अंदर एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। इस देश के लिए हम यह कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक आपदाओं का देश है क्योंकि इस देश के अंदर किसी न किसी हिस्से में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से लोग पीड़ित रहते हैं। लोगों के सामने समस्याएं रहती हैं। किसी जगह भीषण अकाल की समस्या रहती है तो कहीं बाढ़ की समस्या रहती है, कहीं प्राकृतिक तूफान की समस्या रहती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं जिससे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। इस प्रकार की समस्याएं इस देश के अंदर आती रहती हैं। 50 साल की आजादी के बाद भी हम इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं जिससे इन प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिल सके। पंडित जवाहर लाल जी के जमाने में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने का एक प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन यह योजना कार्य रूप में नहीं आ पायी इसी कारण से 50 साल के बाद भी आज जैसी भी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं हम उनसे जूझते रहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि अकाल, सूखे और पेयजल की समस्याओं के ऊपर चर्चा हो और इस हाउस के अंदर पार्टी के स्तर से नहीं उठकर केवल राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहें। यह हमेशा होता रहा है जब जब भी चर्चा हुई है। एक दूसरी सरकार या एक दूसरी पार्टी की सरकार के ऊपर लांछन लगाकर इन चर्चाओं को समाप्त कर दिया जाता है। उस समस्या को दूर करने के लिए जो भी कमियां या खामियां रही हैं या जो भी आर्थिक या पैसे की समस्या के कारण हम उस समस्या को दूर करने में काम नहीं कर पा रहे हैं उसकी ओर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की बात हो, ध्यान नहीं जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए जितना पैसा चाहिए आज देश के

अंदर राज्य सरकारें उसके लिए सक्षम नहीं हैं। चाहे राजस्थान सरकार की बात करें, चाहे गुजरात सरकार की बात करें, चाहे आन्ध्र प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे उड़ीसा सरकार की बात करें, सारी सरकारों के मुख्य मंत्रियों ने वहां की सरकार की आर्थिक स्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार से उसके प्राकृतिक आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता चाही है । केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण भी विशाल होना चाहिए । राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने नवंबर महीने में 1145 करोड़ रुपये की सहायता के लिए एक ज्ञापन दिया था । उसके उस ज्ञापन के आधार पर केन्द्र सरकार ने 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । इसी प्रकार से गुजरात की सरकार के ज्ञापन की बात करें, चाहे आन्ध्र प्रदेश की सरकार के ज्ञापन की बात करें, यह एक ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में हमारा दृष्टिकोण मानवीय आधार पर आधारित होना चाहिए, ताकि लोगों को खाने के लिए अनाज मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके । लेकिन आज राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति अन्य प्रदेशों से अलग है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं और हमेशा भीषण अकाल का संकट बना रहता है । अब राजस्थान में लगातार तीसरे साल भीषण अकाल है । आज लोगों के सामने मज़दूरी की बात तो अलग है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है, जानवारों को बचाने के लिए चारा नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : मीणा जी, अब आप समाप्त करिए ।

**श्री मूलचन्द मीणा** : इस संकट को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार ने अकाल राहत कार्य भी शुरू किए हैं । लेकिन राजस्थान की सरकार के पास जितना पैसा है, उसके हिसाब से कार्य तो बहुत स्वीकृत किए हैं, लेकिन उन्हें आरंभ नहीं कर पाई है । इसलिए केन्द्र सरकार को भी चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण बदलते हुए राजस्थान सरकार की अधिक से अधिक सहायता करे । मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप प्रधान मंत्री जी से कहिए कि आपने गुजरात का दौरा तो किया है, राजस्थान का भी आप दो दिन का दौरा करें । राजस्थान में जो भीषण अकाल है उसका आप जायजा तो लें । तभी तो प्रधान मंत्री जी को दया आएगी और ज्यादा राशि मिल सकेगी । राजस्थान के मुख्य मंत्री जी बेचारे गांव-गांव जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा, जब उनके पास पैसा ही नहीं है । वह तो पहले ही कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । फिर भी वह कोशिश कर रहे हैं । फिर भी राजस्थान की सरकार कोशिश कर रही है । मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान की सरकार सारा ही काम

पूरा कर रही है । जितना अकाल पड़ा हुआ है और भीषण अकाल से जो लोग पीड़ित हैं, उन सब को सहायता पहुंचा तो रही है, लेकिन वह पूर्णरूपेण सहायता पहुंचा नहीं पा रही है । राजस्थान में जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे-वैसे वहां चारे और पीने के पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है । इसलिए समय रहते, केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को पूर्णरूपेण सहायता पहुंचाई जानी चाहिए । आज राजस्थान में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है । अभी तो अप्रैल का महीना है, मई और जून के महीने तो अभी शेष हैं । ऐसी भीषण स्थिति के अंदर पशुओं और मनुष्यों को, विभिन्न प्रकार की बेवक्त, बेमौसमी बीमारियां जो होती हैं, उनके हो जाने का अंदेशा है । वहां के लोग ऐसी बेमौसमी बीमारियों से पीड़ित हो कर मरना शुरू हो जायेंगे । इसलिए माननीय मंत्री जी आप अपना विशाल दृष्टिकोण अपनाते हुए, मानवीय आधार पर, अकाल की इस भीषण समस्या से निपटने के लिए, राजस्थान सरकार की अधिक से अधिक सहायता करें । यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । जयहिन्द ।

**प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज अपने देश का एक बहुत बड़ा भू-भाग अकाल के साये के अंतर्गत आ गया है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश का ज्यादातर जो भाग है, वह इस समय सूखे के साये से प्रभावित है । केन्द्रीय सरकार ने समय रहते इस विषय में कदम उठाए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए सहायता का देशव्यापी आह्वान किया है और सूखे की समस्या का निदान खोजने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग भी बुलाई है । रेलवे विभाग ने निशुल्क चारा और पानी भेजने की व्यवस्था की है और मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी ।

महोदय, मैं इस विषय में कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं जैसाकि मेरे बहुत से साथियों ने दिए। महोदय, मेरी मान्यता है कि इस देश में वन-सम्पदा, भू-सम्पदा और खनिज सम्पदा का कोई अभाव नहीं रहा है । जल-सम्पदा का भी कोई अभाव नहीं है और बरसात के मौसम में प्रचुर मात्रा में बरसात होती है, लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों में आम लोगों को पीने के लिए पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है । महोदय, मैं मानता हूं कि ईश्वर का इस में कोई दोष नहीं है । अगर कहीं दोष है तो हमारे जल-प्रबंधन में है । अगर जल-प्रबंधन की ओर ठीक से ध्यान दिया गया होता, विशेषकर जब देश आजाद हुआ, तो यह स्थिति निर्मित ही नहीं होती ।

मान्यवर, जब मैं विद्यार्थी था तो सुनता था कि गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना बन रही है, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी उल्टे गांव-गांव में जो तालाब थे, बावलियां थीं, छोटी-मोटी नदियां थीं, वह भी सूख गयीं। आज परिस्थिति यह है कि बरसात के मौसम में जब तेज बारिस होती है तो बाढ़ से तबाही तो होती ही है, बहुमूल्य जल भी बहकर समुद्र में चला जाता है जिसे हम रोक नहीं पाते और इस तरह के अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है । इस दिशा में सुनियोजित ढंग से कार्य होना चाहिए था । महोदय, मेरा सरकार को सुझाव है कि जल-प्रबंधन के लिए सार्थक प्रयत्न होने चाहिए । मैं ने सुना है कि राजस्थान में लोगों ने प्रयत्न कर के गांवों में कई बावलियों को मिलाकर एक छोटी मोटी नदी बहा दी है । अगर इस तरह के प्रयास होंगे तो मैं समझता हूं कि देश में जल का कतई अभाव नहीं रहेगा । इसलिए सरकार को इस दिशा में उचित कदम शीघ्र उठाने चाहिए और विशेषकर वाटर-शेड के कार्य पर ध्यान दिए जाने चाहिए । अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं । गुजरात सरकार ने कई बावलियां बनाने और चैक डैम बनाने का जो काम हाथ में लिया है, वह देशव्यापी स्तर पर किया जाना चाहिए ।

महोदय, दूसरी एक खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के वन विभाग द्वारा एक बड़ा गलत कार्य हुआ है । मैं ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में देखा है कि जहां अच्छी जमीन है, वहां बड़ी भारी संख्या में यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए हैं । महोदय, यह पेड़ जमीन के अंदर से पानी को बहुत तेजी से खींचता है और जमीन का वाटर लेवल निरंतर नीचे चला जाता है । दरअसल, इस तरह के पेड़ों की आवश्यकता इस देश में है ही नहीं। यह पेड़ तो आस्ट्रेलिया, डार्लिंग के दलदल वाले एरिया में लगाए जाते हैं । मेरा मानना है कि इस देश से यूकेलिप्टस को खत्म किया जाना चाहिए और उस की जगह छायादार, फलदार देसी वृक्ष लगाए जाने चाहिए । चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने बोलने के लिए समय दिया ।

**श्री बालकवि बैरागी** (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने के लिए समय दिया । महोदय, यह चिंता का विषय है और मुझे संदेह है कि आप की घंटी जल्दी बज जाएगी और आप कहेंगे कि समय हो गया । इसलिए मैं दो-तीन मिनिट चाहता हूं और आप को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा ।

महोदय, आज जो सदन की चिंता का विषय है, उस में मुझे महाकवि बंकिम का 'वंदे मातरम्' गीत याद आता है । बंकिम बाबू ने मां की वंदना 'सुजलाम' से शुरू की थी । उस गीत में हम 'सुजलाम्' से शुरू होकर 'वंदे मातरम्' तक आते हैं और कहते हैं, 'सुजलाम् सुफलाम्, मलयज शीतलाम् ।' लेकिन आज यह सदन और पूरा देश चिंतातुर होकर भारत माता के उस रूप की तरफ देख रहा है जिसे हम 'सुजलाम्' कहा करते थे ।

महोदय, यह विषय चिंता का है और मैं मानता हूं कि सदन में चार, सवा चार घंटे से जो चर्चा चल रही है, वह निरर्थक नहीं होगी बल्कि सार्थक होगी। उसमें से कई सारी महत्वपूर्ण बातें बाहर आएंगी । हम निराशा वाले लोग नहीं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस संकट को हम पार पटक देंगे ।

एक बात को मेरा सौभाग्य है कि यह जो कृषि मंत्री का प्रभार लेकर सामने बैठे हुए हैं, श्री सुंदर लाल जी पटवा, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं और हम दोनों एक ही शहर के, एक ही तहसील के, एक ही जिले के रहने वाले हैं । प्रदेश तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन हम एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनकी छाया में चलकर के, पलकर के हम बड़े हुए और इन समस्याओं को ये भी जानते हैं, मैं जानता हूं और मुझे पता है कि ये उत्तर देंगे, ये सोचेंगे, विचार करेंगे लेकिन चाहे इनका घर हो या मेरा घर हो, आपका घर हो माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय या आपमें से किसी का निवास हो, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों के सरपंचों के जगह-जगह टेलिफोन आते हैं, दौड़-दौड़ कर वे आते हैं और वे हमसे सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपकी जो सांसद निधि है, उसमें से कुछ पैसा दे दीजिए ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए । वे हमसे पानी के लिए पैसा मांगते हैं, चलकर के आते हैं और जब हम उनको पैसा देते हैं, स्वीकार करने की बात करते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि साहब, यह कब तक सैंक्शन होकर आ जाएगा ताकि हमारे यहां काम चल जाए । एक तो मैं सरकार से यह चाहूंगा, पटवा जी से भी चाहूंगा कि थोड़ा इस दिशा में सोचकर के कुछ बातचीत कर लें, शौरी जी से बातचीत कर लें कि अगर पानी के लिए हम लोगों ने कुछ पैसा दिया है तो उसको रोकें नहीं, वह रुके नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कल ही अपील हुई है, बहुत बड़ी अपील हुई है, अटल जी ने अपील की है और सारे देश से उन्होंने कहा है कि सारे मिलकर के सहायता करें । उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने स्वयं बहुत सारी बातें कही हैं, गुजरात में तो मैं स्वयं होकर आया हूं, 12 मार्च को वहीं था, राजकोट का परिदृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, आते ही मैंने सबको सूचित भी किया । गोलियां चल चुकी थीं वहां पर, पानी के लिए लोग मर चुके थे और आन्दोलन चल रहे थे । मैं किसी भी सरकार पर अंगुली उठाने के लिए कोई भी पेशकश अपनी तरफ से नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए । कौन सरकार चुस्त थी, कौन सुस्त थी, इस बात को छोड़ दीजिएगा लेकिन कुल मिलाकर के हमारा मानस क्या है, इस पर जरूर हमको विचार करना पड़ेगा और यदि हम यह नहीं करेंगे तो खुद को धोखा देंगे । इसलिए मैं अर्ज़ यह करना चाहता हूं कि आपने जो पैसा आबंटित किया है राज्यों को वह उनको दिया जाना चाहिए । मैं मध्य प्रदेश पर ही फोकस करके बात करूं तो शायद पटवा जी मुझसे

असहमत नहीं होंगे, उन्हें खुद को पता है, पेपर उनके पास भी हैं, मध्य प्रदेश ने आपसे सूखे के लिए जो कुल पैसा मांगा वह 361.60 करोड़ मांगा और आपने कुल 39 करोड़ दिया । पता नहीं वह वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं नहीं जानता, सरकार को मिला भी सही या नहीं क्योंकि आबंटित करना अलग चीज है और उसको दे देना अलग चीज है । यह भयावहता कहां तक है, मैं लम्बी-चौड़ी लिस्ट नहीं बताना चाहता लेकिन मध्य प्रदेश के कुल 7 जिलों में गंभीर स्थिति है और वे 7 जिले हैं - खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, रायसेन, होशंगाबाद, रायपुर । होशंगाबाद जिले से हमारे कृषि मंत्री खुद चुनाव लड़कर आते हैं । जहां तक इस अकाल की प्रेत-छाया में हम लोग जी रहे हैं, उस प्रेत-छाया की अगर मैं लिस्ट दूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, जिससे स्वयं कृषि मंत्री जी सहमत होंगे, तो वह होते हैं 27 जिले - धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, रतलाम, इंदौर, सीधी, शहडोल, उमरिया, रायगढ़, जशपुर नगर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर - हम दोनों के जिले, राजगढ़ - मुख्य मंत्री जी का जिला, खंडवा, मंडला, छिंदवाड़ा, रीवा, गुना, दतिया, पन्ना, बैतूल, रायपुर, उज्जैन, देवास और शाजापुर। अब यह अकाल की प्रेत-छाया 27 जिलों पर है इस वक्त भी और जितनी देर होती जाएगी यह छाया और लम्बी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी । यदि हम नहीं जागे, नहीं चेते तो हमको बहुत परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि 27 तहसीलें और 7 जिले तथा 3240 गांव तो सूखे की गंभीर चपेट में हैं और हम लोग वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं ।

मेरे दो-तीन छोटे-छोटे सुझाव हैं उन पर आप विचार कर लीजिएगा । यह अप्रैल का महीना है और अभी भीषण गर्मियां आने वाली हैं, आपके पास मौसम का पूरा विभाग है, मौसम विभाग में जो भी आपके कर्मचारी, अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जरा उनसे आप बातचीत कर लीजिए और पूर्वानुमान लगाइए कि कब कहां पर क्या हो सकता है । पूर्वानुमान अगर आपने नहीं लगाया तो लू से लोग मरना शुरू हो जाएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के हिस्से में और हम पानी के मारे तो तड़प ही रहे हैं । अक्तूबर से लेकर दिसम्बर के बीच में आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि कहां-कहां अकाल हो सकता है और दिसम्बर से लेकर मार्च महीने तक आपको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि कहां-कहां आगे बाढ़ की संभावनाएं हो सकती हैं ।

अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करने की कृपा करें तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा न्याय कर सकेंगे । एक चीज और मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति हैं । आप भी उनका नाम जानते हैं, आप वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं । एक व्यक्ति हैं जो आज वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के जल सलाहकार हैं । उनका नाम है डॉ. श्रॉफ । उन्होंने पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है । इस क्षेत्र में उनकी बहुत उपलब्धियां हैं । मध्य

प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं सरफेस वॉटर के मामले में ऐक्सपर्ट हैं । आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है इस चीज को । अभी पिछले दिनों वे विदेश में गए थे तो उनको एक विशेष इनाम इस बात के लिए दिया गया कि पानी की समस्या से लड़ने के लिए जनजागरण तैयार करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सारी बातों पर विचार करें ।

महोदय, अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं । मेरे पास बहुत है कहने को लेकिन समय की सीमा है । मैं एक निवेदन कर दूं आपसे कि जो हैंड पंप सूख गए हैं, उनको रिचार्ज करने के लिए कोई योजना है आपके पास ? दूसरा जो कुएं सूख गए हैं, मेरे और इनके जिले में डेढ़ लाख कुएं हैं, डिग वैल्स डेढ़ लाख हैं । हम दोनों गर्व से कहते थे कि हमारे जिले में डेढ़ लाख कुएं हैं । वे डेढ़ लाख कुएं सूख गए हैं । अगर आप वहां ट्यूबवैल डालेंगे या हैंड पंप डालेंगे तो 800 फीट तक पानी नहीं है । मालवा की बैल्ट में 800 फीट नीचे से पानी निकलेगा और वह होगा सॉल्टी वॉटर, नमकीन पानी होगा और वह पीने के काम का नहीं है । आप वहां इंस्ट्रक्शंस दें कि किसान उन कुओं को मिट्टी से भरना न शुरू कर दें । इस पर प्रतिबंध लगाइए और दूसरी ओर कहीं किसान हैंड पंपों से खूंटे की तरह बैल न बांधने लग जाएं । इसके लिए जरा नये सिरे से रखवाली करने के लिए निर्देश दे दीजिएगा ।

महोदय, अब मैं अंतिम बात कहकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । आपसे 3 चीजें मांगी गई हैं - फूड, फंड और फौडर । ये 3 चीजें मांगी गई हैं । इनको जल्दी दीजिएगा । इनको रोकिए मत । जहां रेल से जा सकता हो, रेल चलाइए, जहां दूसरा कोई ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, उसका इंतजाम करिए । चारे को रोकिए मत । अगर चारा रुकेगा तो हमारे पशु धन का बहुत नुकसान होगा । मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जब उनसे कहा गया कि गेहूं का भूसा बाहर जा रहा है तो मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल करके कहा कि राजस्थान में भी अकाल है, पशु मर रहे हैं, आंख मूंद लीजिएगा और चारे को जाने दीजिएगा और उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी।

मंत्री जी, मुझे आपसे एक विशेष निवेदन करना है । अगर आप इस मामले में थोड़ी गंभीरता से विचार करके इस ओर ध्यान देंगे, तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगा । महोदय, अभी तक प्रैक्टिस यह थी कि प्रदेश सरकार आकर कहती थी कि हमारे यहां सूखा है, हमारे यहां बाढ़ है । कृपा करके आप अपने मॉनीटरिंग सैल की व्यवस्था करके पूछना शुरू करिए कि क्या स्थिति है आपके प्रदेश में । आप कब पहल करेंगे ? दिल्ली कब पहल करेगी ? अगर दिल्ली पहल नहीं करेगी और वहीं से समाचार आने का आप इंतजार करते रहेंगे तो हम लोग उलझते चले जाएंगे । इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है ।

किसी भी राज्य के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता । मैंने इस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। शायद मेरी ये दो-चार पंक्तियां कहीं आपके ज़हन में रह जाएं । मैंने कहा है कि -

साबरमती तड़प कर बोली
जयपुर से भोपाल से,
लव कुश करने लगे गुजारा
जब पेड़ों की छाल से ।
तो
उठो समय के राम,
संभालो शस्त्र
और अब खुल कर
लड़ो अकाल से ।

मैं कह रहा हूं कि अकाल से लड़ने का समय अब आ गया है । मैं बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि -

साबरमती तड़प कर बोली
जयपुर से भोपाल से,
लव कुश करने लगे गुजारा
जब पेड़ों की छाल से ।
तो
उठो समय के राम,
संभालो शस्त्र
और अब खुल कर
लड़ो अकाल से ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं

और इस सदन के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब आसन पर हैं तो हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह सदन सोया हुआ सदन नहीं है, यह सदन लापरवाह लोगों का सदन नहीं है । यह सदन आश्वस्ति देने वाला सदन है । यह सदन जनता की पीड़ा और जनता के फफोलों से पूर्णतया अवगत है और हम इस लड़ाई को यहां से शुरू करना चाहते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to associate myself with the sufferings of the people because of the drought in various parts of the country. I represent the North-Eastern Region, which is the other way round. It is a flood-affected area. We have surplus water, and very rarely we face drought. I am incompetent to suggest to the Government about the specific measures. What I would suggest and request the Government is that adequate relief and rehabilitation measures should be taken immediately.

Sir, from my experience, I would say that we must have a rescue force from the Central Government. Every time we have to depend on the State Government. We supply relief materials, but so far as the rescue operation is concerned, both during floods and drought, there should be a mobile rescue force on which we can rely, which can rush to the spots where they are required, on which we can rely because special assistance is required for particular areas. This force should be able to assist in transport of water from water-surplus areas, or flood-affected areas to drought-affected areas. Also, most of the forces, including the Army, deployed in rescue operations during flood situations, are afraid of taking up these operations because of inexperience. Therefore, for both these purposes, we must have a specific rescue teams of experts and the workforce with the Central Government to meet these kinds of situations. We are facing this problem because of global warming and we will have to face it more and more because it is just the beginning. I would request the Government to take adequate steps so that we can face any such situation in the future.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : अकाल पर जो अल्पकालिक चर्चा नियत थी वह समाप्त की जाती है।

**श्री राजूभाई ए. परमार** : सर, इस पर रिप्लाई कल के लिए रखा जाए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : माननीय कृषि मंत्री, अपना जवाब कल सदन में देंगे। कृषि मंत्री, खोपरा एवं पटसन मूल्य नीति पर अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखेंगे। माननीय सदस्य, इस संबंध में स्पष्टीकरण कल पूछ सकते हैं।

## STATEMENT BY MINISTER

### Price policy for copra for 2000 Season and price policy for raw jute for 2000-2001 season

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SUNDER LAL PATWA): Sir, I lay a statement on the Table of the House regarding price policy for copra for 2000 season and price policy for raw jute for 2000-2001 season. [*Placed in Library See* No. *LT 1703/00*]

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी)** : सदन की कार्रवाई कल बुद्धवार, 26 अप्रैल, 2000 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at twenty-eight minutes past Eight of the clock, till eleven of the clock, on Wednesday, the 26th April, 2000